कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

अश्विन–कार्तिक 2078, अक्टूबर 2021

ई–कॉमर्स कंपनियों का है भ्रष्टाचार से पुराना नाता

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांतीय विचार वर्ग, त्रिपुरा

(2–3 अक्टूबर, 2021)

सचित्र झलक

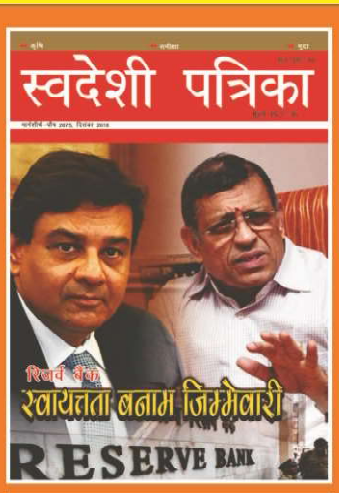

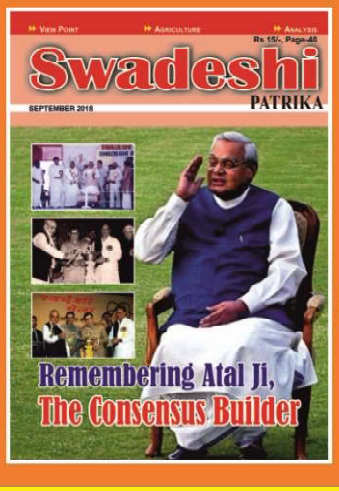

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI
Patrika

स्वदेशी
पत्रिका

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–29, अंक–10
अश्विन–कार्तिक 2078 अक्टूबर 2021

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **34-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

ई–कॉमर्स कंपनियों का है भ्रष्टाचार से पुराना नाता

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आजकल
मुडीज की रेटिंग में अर्थव्यवस्था सकारात्मक
.....अनिल तिवारी

10 टेलीकॉम
टेलीकॉम कंपनियां संकट में हैं या सरकार पर दबाव बनाने के खेल में!
..... विक्रम उपाध्याय

12 पर्यावरण
वायु प्रदूषणः अगर इच्छाएं द्रुतगामी होती...
.....केके श्रीवास्तव

14 विचार
शहरीकरणः एक एकीकृत रूप
.....डॉ. जया कक्कड

17 आर्थिकी
मुद्रीकरण योजना– खजाना ढूँढने का प्रयास
.....अनिल जवेलकर

19 खेतीबारी
शहरी विकास के लिए खेती से खिलवाड़
..... देविन्दर शर्मा

21 विश्लेषण
लोकतंत्र और आम आदमी की जागरुकता
..... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

24 मुद्दा
तेल के ऊँचे दामः लाभ भी, संकट भी
.....डॉ. भरत झुनझुनवाला

26 बीच-बहस
चीन की बिजली गुल, भारत पर कैसे पड़ेगा असर
..... दुलीचंद कालीरमन

28 आत्मनिर्भर
''युवा, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत''
..... अभिषेक प्रताप सिंह

30 नारी शक्ति
'भारतीय संस्कृति के मूल में है महिला सशक्तिकरण'
..... डॉ. अनुपमा अग्रवाल

32 बहस
शिक्षा और पर्यावरण तन्त्र डुबा रहा है अर्थव्यवस्था को
.....स्वदेशी संवाद

पाठकनामा

बे–रौनक है बाजार

त्यौहार का मौसम शुरू हो चुका है। आमतौर पर इस मौसम में आम आदमी घर की आवश्यक जरूरतों के साथ–साथ नया घर, गाड़ी, टीवी, फ्रीज जैसे अत्यंत उपयोगी सामानों की खरीदारी करता है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर झेलने के बाद आया दशहरा और दीपावली का त्यौहार निराश करने वाला और बिल्कुल ही बेरौनक लग रहा है। दिल्ली सहित एनसीआर के इलाके में बिल्डरों के बनाए लाखों फ्लैट खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ता में घर खरीदने को लेकर कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। देश में बुनियादी ढ़ांचे को लेकर अध्ययन (सर्वेक्षण) करने वाली एक संस्था के हालिया सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में मकानों की बिक्री में पूर्व की तुलना में 12 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि इस अध्ययन रिपोर्ट में इसी दरमियान देश के कुछ छोटे शहरों में मकानों की खरीद बेच की गतिविधियां बढ़ने के भी संकेत मिले हैं। लेकिन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में यह दर बिल्कुल ही घटी हुई है। कोलकाता में 22 फ़ीसदी, चेन्नई में 18 फ़ीसदी, मुंबई में 16 फीसदी तथा दिल्ली एनसीआर में 12 प्रतिशत की कमी आंकी गई है।

भवन निर्माण के क्षेत्र में यह शिथिलता अकस्मात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह सीता की तरह साफ है केंद्र की सरकार ने काला धन छिपाने और अवैध तरीके से सामान खरीदने पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नियम कानून कड़े कर दिए हैं। वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्तियों की खरीद बेच पर भी एक तरह से अंकुश लगा है। इन नियमों का भवन निर्माण क्षेत्र पर भी असर पड़ा है। इसी दौरान कोरोना की महामारी के चलते देश में हुई पूर्ण तालाबंदी ने भी इस कारोबार की कमर तोड़ दी है। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए ढ़ेर सारी सुविधाएं, सहूलियत देने की घोषणा की है, लेकिन डरे–सहमे खरीददारों की उदासीनता के कारण बाजार से रौनक गायब है।

अत्यंत जरूरत होने के बावजूद लोग मकान नहीं खरीद रहे हैं तो सरकार को विश्वास बहाली के लिए कुछ जरूरी कारगर उपाय लेकर सामने आना चाहिए तभी समाज का हित संभव होगा।

गार्गी तिवारी, नोएडा, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

भारत को अपनी युवा शक्ति और उनके योगदान के बल पर बहुत विश्वास है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के आदर्श को प्राप्त करने के लिए देश आगे बढ़ रहा है। हमारा मानना है कि अगर हमें जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें दूसरों को खुश करना सीखना होगा।

रामनाथ कोविन्द
राष्ट्रपति, भारत

मैं वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्ट–अप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे उत्पादों पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं, जो न केवल लोगों के स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे किसानों और युवाओं की आय बढ़ाने में भी मदद करते हैं।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

स्वदेशी जागरण मंच डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय समझौतों या आरसीईपी जैसे बहुपक्षीय समझौतों के खिलाफ है। भारत के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए देशों के साथ अलग–अलग व्यवहार करना कहीं बेहतर विकल्प है।

डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

भारत से उड़ते जा रहे बड़े भारतीय यूनिकॉर्न

भारत को अपने स्टार्टअप पर अत्यधिक मूल्य बढ़ाने और देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान पर गर्व है। हमारे यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन के साथ स्टार्टअप) हमारे प्रतिस्पर्धियों की ईर्ष्या का कारण हो सकते हैं। लेकिन यह जानकर हमारी खुशी कम ही रह जाती है कि उनमें से कई अब भारतीय नहीं रहे। इनमें से अधिकांश बड़े हुए स्टार्ट–अप अब भारतीय कंपनियां नहीं हैं, फ्लिप हो चुकी हैं। हमें यह कहते हुए गर्व हो सकता है कि दो भारतीय लड़कों ने लिपकार्ट बनाया, जिसका बाजार मूल्यांकन अंततः 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गया। लेकिन तथ्य यह है कि लिपकार्ट के प्रमोटर भारत से पहले ही दूर हो गए थे और अपनी कंपनी और अन्य संबद्ध कंपनियों को सिंगापुर में पंजीकृत कर लिया था, और बाद में कंपनियों के समूह को वॉलमार्ट को बेच दिया गया था (जब 77 प्रतिशत शेयर वॉलमार्ट को हस्तांतरित कर दिए गए थे)। यानि एक यूनिकॉर्न जो पहले ही उड़ गया था, एक विदेशी कंपनी के हाथों में चला गया, और इसके साथ भारतीय बाजार की हिस्सेदारी भी एक विदेशी कंपनी को आसानी से हस्तांतरित कर दी गई।

एक भारतीय कंपनी की फ्लिपिंग का मतलब एक ऐसे लेनदेन है जहां एक भारतीय कंपनी एक विदेशी क्षेत्राधिकार में एक अन्य कंपनी को पंजीकृत करती है, जिसे बाद में भारत में सहायक कंपनी की होल्डिंग कंपनी बना दिया जाता है। भारतीय कंपनियों के लिए सबसे अनुकूल विदेशी क्षेत्राधिकार सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन हैं। 'फ्लिप' लेनदेन के रूप में लागू करने के तरीकों में से एक शेयर स्वैप के माध्यम से है। इसके तहत, भारतीय प्रमोटरों द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी को शामिल करने के बाद, घरेलू कंपनी के शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों की विदेशी होल्डिंग कंपनी के शेयरों के साथ अदला–बदली की जाती है। परिणामस्वरूप, घरेलू कंपनी के शेयरधारक विदेशी होल्डिंग कंपनी के शेयरधारक बन जाते हैं। शेयर स्वैप के स्थान पर, एक लिप संरचना भी निष्पादित की जा सकती है जब भारतीय कंपनी के शेयरधारक विदेशी होल्डिंग कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और होल्डिंग कंपनी अपने शेयरधारकों से भारतीय कंपनी के सभी शेयरों का अधिग्रहण करती है।

ग़ौरतलब है कि सैकड़ों भारतीय यूनिकॉर्न या तो फ्लिप हो गए हैं या विदेशी हो गए हैं, जिनके भारतीय संस्थापकों ने उन्हें भारत में शुरू किया था। उनमें से अधिकांश का परिचालन यानि कार्य क्षेत्र भारत में है और उनका प्राथमिक बाजार भी भारत में है। लगभग सभी ने भारतीय संसाधनों (मानव, पूंजीगत संपत्ति, सरकारी सहायता, आदि) का उपयोग करके अपनी बौद्धिक संपत्ति (आईपी) विकसित की है। सवाल है कि भारतीय यूनिकॉर्न देश छोड़कर जाना क्यों चाहते है? इसका सीधा जवाब है –1. भारतीय नियामक परिदृश्य, भारतीय कर कानूनों और भारतीय अधिकारियों द्वारा जांच से बचना, 2. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अपनी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों को विदेश जाने के लिए मजबूर करते हैं और कभी–कभी इसे इन स्टार्टअप्स में अपने निवेश के लिए एक शर्त के रूप में भी रखते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि डेटा और आईपी का मुख्यालय विदेशों में हो जहां वे अपना पैसा लगाएंगे, 3. अधिकांश व्यवसाय विदेशी निवेशकों से है और ये निवेशक केवल विदेशी मूल कंपनी के साथ अनुबंध करना चाहते हैं, 4. अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों ने जो अनुकूल निवेश नीतियां अपनाई हैं, वे भी स्टार्टअप और निवेशकों को आकर्षित करती हैं, 5. निवेशकों के एकत्रीकरण के कारण मूल्यांकन अधिक है, इस धारणा के साथ विदेशों में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने की इच्छा।

भारतीय यूनिकॉर्न देश से बाहर भाग तो जाते है पर उनके फ्लिपिंग से – 1. राजस्व की हानि, 2. महत्वपूर्ण डेटा के साथ–साथ आईपी का स्वामित्व विदेशों में स्थानांतरित किया जाता है, 3. भारतीय कानूनों की अवहेलना कर फ्लिप किए हुए स्टार्टअप अपने घरेलू समकक्षों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, 4. विदेशी मुख्यालय संरचनाओं के कारण, भारत सरकार इन कंपनियों को समर्थन देने वाले धन के स्रोत का निर्धारण नहीं कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में युद्ध जैसी गतिविधियों की स्थिति में राष्ट्र के लिए सुरक्षा के खतरे हो सकते हैं, 5. विदेशी निवेशकों को अनुचित लाभ देनाः विदेशी निवेशक भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के इच्छुक हैं और फ्लिपिंग से इन्हें भारत में प्रवेश किए बिना यह लाभ उठाना सम्भव हो जाता है। यह एक दुष्चक्र को गति देता है, 6. भारतीय सार्वजनिक इक्विटी बाजारों को गहराई प्राप्त नहीं करने देने आदि का राष्ट्रीय आर्थिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

फ्लिपिंग एक जीता जागता उदाहरण है कि भारत में कैसे विदेशियों के लिए लाल कालीन बिछाए जाते हैं और स्वदेशी खिलाड़ी लालफीताशाही के शिकार हैं । विभिन्न राज्यों में भूमि आवंटन के दौरान विदेशी संस्थाओं को छूट मिलती है, लेकिन स्वदेशी खिलाड़ियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। फ्लिप की गई इकाई को पूंजी तक आसान और सस्ती प्राप्त होती है और साथ ही (डीटीएए का उपयोग करके) निवेशकों को पैसा निकालना बहुत आसान होता है। यहां तक कि भारत में निवेश करने वाले भारतीय फंडों को भी अपने विदेशी समकक्षों की तुलना में अधिक पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना पड़ता है।

भारत में पंजीकरण के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी तक पहुंच से लेकर, नीति, विनियमों सहित व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। स्वदेशी निवेश संस्थाओं के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण नीतियों को रोकने की जरूरत है।

केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। अंततः भारतीय स्टार्ट–अप को फ्लिप करने के लिए हतोत्साहित करने के लिए, हमें कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी, जिसमें फ्लिप करने वालों को विदेशी कंपनी घोषित करना शामिल है।

ई–कॉमर्स कंपनियों का है भ्रष्टाचार से पुराना नाता

अमेजॉन द्वारा हाल ही में सरकार को दिए गए वित्तीय दस्तावेजों से यह पता चल रहा है कि अमेजॉन की 6 कंपनियों द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षों 2018–19 और 2019–20 के दौरान 8456 करोड़ रूपए यानि लगभग 1.2 अरब डालर की राशि कानूनी एवं व्यावसायिक फीस के नाते खर्च की। यह कंपनी की कुल प्राप्तियों, 42085 करोड़ रूपए का 20.3 प्रतिशत था। सबसे ज्यादा कानूनी और व्यवसायिक फीस 3417 करोड़ रूपए बंगलौर स्थित अमेजॉन सेलर सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दी गई। इसी तरह से बाकी कंपनियों ने भी अपने वित्तीय दस्तावेजों में दिखाया है कि उन्होंने भी भारी राशि कानूनी फीस में दी।

कोई भी कंपनी यदि अपने दस्तावेजों में इतनी बड़ी मात्रा में राशि कानूनी एवं व्यावसायिक फीस देती है तो मतलब साफ है कि इसकी आड़ में उन्होंने अपने पक्ष में फैसले कराने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी है। व्यापारी संगठन कांफ्रेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सीधे–सीधे आरोप लगाया है कि लीगल फीस की आड़ में अमेजॉन ने रिश्वत बांटी है। कैट ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर यह कहा है कि चूंकि यह मुद्दा देश की अस्मिता के साथ जुड़ा है, इसलिए इस मामले की तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधक कानून के तहत कारवाई की जानी चाहिए। अमेजॉन कंपनी ने कहा है कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उन्होंने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू भी करा दी है।

ई कामर्स कम्पनियों पर शिकंजा कसने की दरकार

बहुत दिनों से यह मांग आ रही थी कि ई–कॉमर्स कंपनियां जो गैरकानूनी तरीके से भारत में प्लेटफार्म की आड़ में ई–कॉमर्स का व्यवसाय करते हुए विदेशी धन के आधार पर भारी डिस्काउंट देते हुए यानि 'कैश बर्निंग मॉडल' के आधार पर देश के बाजारों पर कब्जा कर रही हैं, को बाध्य किया जाए कि वे अपने वित्तीय दस्तावेजों का लेखा परीक्षण (ऑडिट) करवाकर उन्हें सार्वजनिक करें। लेकिन ये कंपनियां अपने दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से बचती रही।

ऐसे में वर्ष 2018 के दिसम्बर माह में वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत डीआईपीपी विभाग में एक प्रेस नोट–2 जारी कर, इन कंपनियों पर यह अंकुश लगाने का प्रावधान रखा कि वे न तो वे अपने से डिस्काउंट देकर माल सस्ता कर बेच सकती हैं, और न ही अपने पास माल

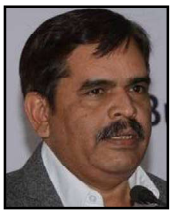

भारत में ई–कॉमर्स मार्केट प्लेस का संचालन करने वाले विदेशी खुदरा विक्रेता भारत के खुदरा एफडीआई कानूनों की धज्जियां उड़ाने के लिए नए–नए मार्ग खोजते रहते हैं।
– डॉ. अश्वनी महाजन

का भंडारण कर सकती हैं। उन पर यह भी शर्त लगाई गई कि वे किसी एक विक्रेता कंपनी के माध्यम से अपनी कुल बिक्री का 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बेच सकती। इसके साथ ही साथ प्रेस नोट–2 में यह प्रावधान भी रखा गया कि ये कंपनियां हर साल सितंबर माह तक अपने वित्तीय कार्यकलापों में कानूनों का पालन हो रहा है, इस बाबत ऑडिटर से प्रमाण–पत्र लेकर उसे अपनी बेवसाईट पर लगाकर सार्वजनिक करेंगी।

प्रेस नोट–2, जो सरकार का नीति दस्तावेज था, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोटिफाई किए जाने की प्रक्रिया के बाद ही इसे कानून बनना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन कंपनियों के द्वारा ऑडिटर से प्रमाण–पत्र संबंधित प्रावधान के अलावा शेष सब प्रावधानों को नोटिफाई कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। बाद में जब भारतीय रिजर्व बैंक को इस विषय की गंभीरता से अवगत कराया गया तो उसने इस प्रावधान को दूसरे रूप में नोटिफाई किया कि ये कंपनियां ऑडिटर से प्रमाण–पत्र लेकर तैयार रखेंगी।

कैसे दी जाती है लीगल फीस के रास्ते रिश्वत?

लीगल और व्यावसायिक फीस के रास्ते रिश्वत देने का तरीका बहुत पुराना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के वक्त में इसका परिमाण बहुत बढ़ गया है। अमेजॉन कंपनी ने अपने लीगल व्यावसायिक कार्यों के लिए कई लॉ फर्मों को रखा हुआ है। इन लॉ कंपनियों को अमेजॉन कंपनी भारी भरकम लीगल फीस देती है, और उसके उपरांत ये कंपनियां किसी दूसरी कंपनी को वह फीस अंतरित करती हैं और उसके बाद एक कड़ी बनती है और अंतोत्गत्वा अंतिम लीगल कंपनी अथवा वकील अथवा कोई प्रोफेशनल राशि नकद निकालकर संबंधित अधिकारियों को देता है। यह काम इतनी कुशलता से किया जाता है कि कंपनी द्वारा सीधे–सीधे रिश्वत देने का मामला नहीं बनता।

समझना होगा कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। जिससे हमारी पूरी सरकारी प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान लगता है। इससे यह भी साबित होता है कि इस कंपनी ने जो भी लाईसेंस और अनुमतियां प्राप्त की हैं, वे सभी कपटपूर्ण तरीके से या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हैं। ऐसे में शुचिता की मांग है कि इन कंपनियों को दिए गए तमाम लाईसेंसों को रद्द किया जाए और इनके तमाम कार्यों को गैरकानूनी घोषित किया जाए। सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जैसे–जैसे सरकारी अफसरों की निशानदेही हो, उन्हें छुट्टी पर भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो।

क्लाउडटेल का मामला

भारत में ईकॉमर्स मार्केटप्लेस का संचालन करने वाले विदेशी खुदरा विक्रेता भारत के खुदरा एफडीआई कानूनों की धज्जियां उड़ाने के लिए नए–नए मार्ग खोजते रहते हैं। हाल तक अमेज़ोन इंडिया ने भारत की जानी मानी सॉफ़्टवेयर कम्पनी के मालिक एनआर नारायणमूर्ति और उनके परिवार के स्वामित्व वाली क्लाउडटेल जैसी कंपनियों के साथ समझौते के माध्यम से सामान को कृत्रिम रूप से सस्ता करने (प्रीडेटरी प्राइसिंग और डिस्काउंटिंग) का कार्य करती रही है, जिससे ऑफलाइन खुदरा व्यापारियों का व्यवसाय ध्वस्त होता रहा है। ध्यातव्य है कि इस संबंध में श्री नारायणमूर्ति की सार्वजनिक आलोचना और अमेज़न के विरुद्ध कार्यवाही शुरू होने के बाद श्री नारायणमूर्ति ने क्लाउडटेल और अमेज़न के समझोते से किनारा कर लिया है।

कंपनी के दस्तावेज़ों के अनुसार उसे चालू वर्ष में माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय से 5,455 लाख रुपये की राशि के साथ–साथ सेवा कर से संबंधित मामलों के लिए ब्याज और दंड के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। यानि माना जा सकता है कि क्लाउडटेल कम्पनी अमेज़ोन की संगत में ना केवल नैतिक रूप से बल्कि क़ानूनी रूप से भी ग़लत कार्यों में संलग्न रही है।

हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 94 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (ई–कॉमर्स) नियम, 2020 प्रस्तावित किए थे।प्रस्तावित नियम उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में ई–कॉमर्स दिग्गज, जो खुद को केवल तकनीकी प्लेटफॉर्म कहते हैं, और वास्तव में पूर्ण विकसित ई–कॉमर्स चला रहे हैं, पर शिकंजा कसने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इन प्रस्तावित नियमों में उच्च छूट के साथ फ्लैश बिक्री को विनियमित करने का प्रस्ताव है और ई–कॉमर्स संस्थाओं के लिए डीपीआईआईटी के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। नियमों में कुछ मौजूदा एफडीआई नीति की तुलना में कुछ परिभाषाओं में संशोधनों के साथ–साथ विक्रेता द्वारा डिफ़ॉल्ट के मामले में ई–कॉमर्स संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने का भी प्रस्ताव है ।

इन प्रस्तावित नियमों का स्वाभाविक रूप से ये कम्पनियाँ तो विरोध कर ही रही हैं, लेकिन हैरानी और खेद का विषय तो यह है के भारत सरकार के ही कई अफसरशाहों और नीति आयोग ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। यह खुलासा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेन्सी रॉयटर्स ने किया है। इस संदर्भ में हाल ही में प्रकाश में आई सम्भावित रिश्वतखोरी और ई कामर्स कम्पनीयों की तरफ़दारी के बीच संबंध की भी जाँच की जानी चाहिए। ❑❑

मुडीज की रेटिंग में अर्थव्यवस्था सकारात्मक

चौतरफा चुनौतियों से जूझकर उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछले हफ्ते सी.एम. आई के आंकड़ों से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद अब यह राहत देने वाली खबर आई है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसका सावरेन आउटलुक नकारात्मक से स्थिर की श्रेणी में कर दिया है। एजेंसी ने हालांकि सावरेन क्रेडिट रेटिंग में कोई बड़ा बदलाव न करते हुए पहले वाला बीएए3 का दर्जा ही बरकरार रखा है, जो कि एक तरह से सबसे निचला इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। सावरेन आउटलुक में बदलाव उन प्रयासों और उनसे मिल रहे पॉजिटिव नतीजों को देखते हुए किया गया है जिनसे गुजरती भारतीय अर्थव्यवस्था ने तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़कर फिर से उठ खड़े होने का जज्बा दिखाया है। रेटिंग एजेंसी के आंकलन में वित्तीय क्षेत्र की बेहतर होती स्थिति को तो रेखांकित किया ही गया है, यह भी कहा गया है कि कई एक नामी–गिरामी सेक्टरों में रिकवरी की रफ्तार उससे तेज रही है, जितनी कि अपेक्षा की जा रही थी।

पिछले 18 महीने से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार की कोशिशों के बावजूद मोटे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था लंगडाकर चलने पर मजबूर है। मौजूदा वित्तीय वर्ष (अप्रैल से जून, 2021–22) की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद 32.4 ट्रिलियन की रही जो कि 2019–20 की पहली तिमाही में 35.7 ट्रिलियन रु. की थी। यह अच्छी खबर है कि साल 2020 के आगे हर महीने क्रमवार जो संकेत निकलकर आ रहे हैं उससे यह भरोसा बढ़ने लगा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना के चंगुल से बाहर निकलकर धीर–धीरे पटरी पर लौट आएगी।

हमें ध्यान रखना होगा कि देश में करोना का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और न ही हमारी इकोनॉमी पूरी तरह उबर पाई है। जैसे टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखी है, वैसे ही एक इकोनॉमी के मोर्चे पर भी लगातार प्रयास जारी रखने होंगे।
– अनिल तिवारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नोट में कहा है कि इस बात के कई साक्ष्य हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड–19 की महामारी के कारण जो गहरे गर्त में चली गई थी अब बाहर आ रही है। सदियों की लंबी मंदी छाया से बाहर निकलते हुए सूरज के उजाले की ओर बढ़ रही है। सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहन के जरिए अनुमानों के विपरीत तेजी से आगे बढ़ रही है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर तीसरी तिमाही में सकारात्मक दायरे में आ

गई है। हालांकि यह 0.1 प्रतिशत रह सकती है। यह बदलाव मुख्य रूप से दो कारणों से हो रहा है। पहला कोविड संक्रमण के दर में कमी लाकर। भारत दूसरी लहर के बाद टीकाकरण पर मुख्य फोकस किया।

अब तक लगभग 100 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश में कोविड संक्रमण की दर न के बराबर रह गई है। और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में उपभोग व्यय से आत्मनिर्भर भारत के निवेश खर्च पर अधिक ध्यान देकर राजकोषीय उपायों के जरिए महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। सीएमआईके अध्ययनकर्ताओं ने पिछले पखवाड़े जारी किए गए अपने सर्वे में बताया था कि छोटे तथा मझौले उद्यमों में काम की गति बढ़ी है। वही फिक्स तनख्वाह पर काम करने की प्रवृत्ति वाली नौकरियों में भी इजाफा हुआ है। सितंबर महीने में एकमुश्त 27 लाख से अधिक नौकरियां लोगों को मिली, जिसमें पारिश्रमिक भी या तो बढ़कर था अथवा वर्तमान बाजार मूल्य के सापेक्ष था। आगे और भी सुनहरा भविष्य होने की कामना की गई है। बताते चले कि सीएमआई प्रमुख महेश व्यास के इस अध्ययन शोध पर कई एक लोगों ने शंका भी जताई थी। कोरोना के पहले आक्रमण के दौरान कामकाजी लोगों के पलायन और कंपलीट लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था ठप्प हो चुकी थी। उस दौरान करोड़ो लोगों की नौकरियां छिन गई थी। सरकार के कल्याणकारी प्रयास से उद्योगों के पहिए धीरे–धीरे हिलना डुलना शुरू हुआ तथा लगा कि जल्द ही देश अपना खोया हुआ पा लेगा। लेकिन करोना की दूसरी लहर ने सारे अनुमानों पर ब्रजपात कर दिया। धन के साथ जन की भी भारी क्षति हुई। आर्थिक अराजकता का माहौल बन गया।

दुनिया के तमाम विकसित देश जो पहली लहर के बाद भारत की ओर ललचाई नजर से देख रहे थे उनकी समझ और सुर बदले हुए नजर आने लगे। भारत पलक झपकते कोरोना से संबंधित आवश्यक दवाईयों का बड़ा निर्यातक के ओहदे से उतर अयातक देश बन गया। छोटे–छोटे देश भी भारत को माक्स, सैनेटाइजर, जीवनरक्षक दवाईयां भेजने लगे। एक तरह से आर्थिक हताशा का हैव्वा खासकर देश के सत्ताविरोधी दलों द्वारा खड़ा किया गया। लेकिन इस दरम्यान देश में कृषि की स्थिति न सिर्फ संतोषजनक रही बल्कि कृषि क्षेत्र ने इस महामारी से निपटने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। सारे सेक्टरों में जब गिरावट के नए–नए किस्से शामिल हो रहे थे उस वक्त कृषि की वृद्धि दर छलांग लगाकर आगे बढ़ने का कारनामा कर दिखाया।

आज देश में 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराकर सरकार मानव जीवन रक्षा के परम लक्ष्य को साधने में सफल हुई है। सीएमआई, मूडीज जैसी नामी रेटिंग एजेसियों के हालिया अध्ययन नतीजे से यह साफ हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यावस्था न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि यह उम्मीद भी जताई गई है कि वास्तविक जीडीपी इसी साल महामारी के पहले स्तर को पार कर सकती है। गौर करने की बात है कि इन पॉजिटिव बदलाव के पीछे उन कुछेक ठोस कदमों की बड़ी भूमिका रही जो वित्तीय तंत्र की कमियों को दूर करने के मकसद से इस बीच उठाए गए। उदाहरण के लिए बैंकों पर बढ़ता एनपीए का बोझ पिछले कई वर्षों से एक बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित किया जाता रहा है। अब अगर इस मोर्चे पर भी हालात को बेहतर होता बताया जाता है तो इसके पीछे एक वजह यह भी है कि नए कानूनों की मदद से गिरती अर्थव्यवस्था देश में बहुत मजबूत हुई है।

जीएसटी संग्रह के नए आंकडें बता रहे हैं कि कर भी पहले की तुलना में कहीं आसानी से और अधिक मिलने लगा है। हालांकि सरकारी खजाने पर दबाव की समस्या अभी भी बनी हुई है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे–जैसे आर्थिक माहौल बेहतर होगा सरकार के लिए वित्तीय घाटा कम करने वाले कदम उठाने की गुंजाइश बढ़ेगी और हालात काबू में आते जाएंगे। चूंकि जोखिम का एक बड़ा स्रोत कोरोना वायरस का संक्रमण भी रहा है। इसकी दूसरी लहर में उठती हुई अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पीछे धकेल दिया था मगर उसके बाद टीकाकरण की तेज मुहिम की बदौलत तीसरी लहर की आशंका काफी कम करने में कामयाबी मिली है। माना जा रहा है कि तीसरी लहर आई भी तो उसका स्वरूप वैसा विनाशकारी नहीं होगा जैसा करोना की दूसरी लहर का था। इस विश्वास ने आर्थिक रिकवरी को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाई है। बहरहाल हमें ध्यान रखना होगा कि देश में करोना का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और न ही हमारी इकोनॉमी पूरी तरह उबर पाई है। जैसे टीकाकरण की रफ्तार बनाए रखनी है। वैसे ही एक इकोनॉमीके मोर्चे पर भी लगातार प्रयास जारी रखने होंगे।

सबसे बड़ी चुनौती अब भी रोजगार के अधिक से अधिक मौके उपलब्ध कराने की है ताकि मांग बढ़े और एकनामी का चक्का रफ्तार पकड़े। आजादी के अमृत महोत्सव के भव्य आयोजनों के बीच केंद्र की सरकार अत्याधिक रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए ढेर सारे विभागों में नवाचार के साथ–साथ वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए शहरों के साथ–साथ ग्रामीण इलाकों में भी निवेश का दायरा बढ़ा रही है। उम्मीए की जा रही है कि इसके फलितार्थ शुभ ही होंगे। ❑❑

टेलीकॉम कंपनियां संकट में हैं या सरकार पर दबाव बनाने के खेल में!

यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि भारतीय दूरसंचार उद्योग दिन प्रति दिन आगे बढ़ रहा है और दूरसंचार कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। इस समय भारत में 116 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ता हैं। जीएसएम एसोसिएशन के अनुसार भारतीय मोबाइल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

७ ायभ ग्प्रसपस

क्या भारत का दूरसंचार उद्योग डूबने की कगार पर है? या भारत का दूरसंचार उद्योग पर किसी खास घराने का एकाधिकार होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दूरसंचार के एक बड़े औद्योगिक समूह ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया है कि वह अब इस क्षेत्र में कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, सरकार चाहे तो उस कपंनी में उसकी हिस्सेदारी को जब्त कर ले, या किसी और निजी कंपनी को दे दे या मन करे तो उसकी इक्विटी को किसी वित्तीय कंपनी को दे दे। यह कंपनी है वोडाफोन के तत्कालिन चेयरमैन और भारतीय उद्योग जगत के जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की।

कुमार मंगलम बिड़ला ने इसी जुलाई में कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी सरकार या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी कंपनी को मुफ्त में देने की पेशकश की। और 4 अगस्त को, श्री बिड़ला ने वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा भी दे दिया।

सरकार भी इस उहापोह में है कि दूरसंचार उद्योग की मांग के अनुसार उनकी सभी देनदारियों को टाल दे, या उनके कहे अनुसार राजस्व भागीदारी के फार्मूले को बदल दे या इस उद्योग के लिए कोई बड़ा पैकेज जारी करे या फिर पूर्व की तरह इन पर उगाही का दबाव डाले।

दरअसल भारत के दूरसंचार उद्योग का निजीकरण किया गया तभी से आज से तक यह उद्योग तमाम विवादों और कानूनों अड़चनों में उलझता आया है। भारत सरकार की निजीकरण की नीति ने सरकारी दूरसंचार कंपनियों को अपनी मौत मरने दिया और तमाम संपतियों और व्यवसाय को निजी हाथों में जाने दिया। अब वहीं निजी कंपनियां सरकार और ग्राहक दोनों को दर्द देने में लगी है। सरकार को राजस्व का हिस्सा नहीं मिल रहा है और नकदी संकट का हवाला देने वाली कंपनियां अब इस क्षेत्र में कोई नया निवेश नहीं कर रही हैं जिसके कारण दूरसंचार क्षेत्र के ग्राहकों को ना तो सही नेटवर्क मिल पा रहा है और ना सही डेटा।

सितंबर के दूसरे सप्ताह में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नकदी संकट से जूझ रहे दूरसंचार उद्योग के लिए राहत पैकेज जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस राहत पैकेज में राजस्व हिस्सेदारी के रूप में देय बकाया के भुगतान के लिए चार साल की मोहलत देने, राजस्व

की गणना में गैर–दूरसंचार सेवा से प्राप्त राजस्व को बाहर करने और अनुपयुक्त स्पेक्ट्रम को सरकार को वापस करने की सुविधा खोलने के विकल्प हो सकते हैं।

वास्तव में देखे तो निजी कंपनियों की सारी लड़ाई समायोजित सकल राजस्व,जिसको एजीआर कहते हैं, को अपने तरीके से परिभाषित कराने की है। दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि सरकार सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं से प्राप्त राजस्व में ही अपनी हिस्सेदारी करे ना कि टेलीकॉम कंपनियों की अन्य मदों से प्राप्त आमदनी में किसी हिस्सेदारी का दावा करे। इस समय सरकार उन वसूली को भी राजस्व का हिस्सा मानती है जो टेलीकॉम कंपनियों के खाते में दर्ज होती हैं, जिनमें शेयर इनकम, रेंट इनकम, प्रापर्टी इनकम और लाभांश भी शामिल होते हैं। इसे लेकर कंपनियां काफी दिनों से अदालती लड़ाइयां भी लड़ रही हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1994 में दूरसंचार क्षेत्र के निजीकरण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) की घोषणा की गई थी। सबसे पहले एक निश्चित लाइसेंस शुल्क के बदले में लाइसेंस जारी किए गए, लेकिन चार साल में ही लाइसेंस शुल्क देकर टेलीकॉम सेवा देने वाली कंपनियां सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो गई और यह तर्क दिया जाने लगा कि निश्चित लाइसेंस शुल्क बहुत अधिक है और सरकार इसके बदले राजस्व की हिस्सेदारी वाली नीति लाए।

वर्ष 1999 में वाजपेयी सरकार ने नई टेलीकॉम नीति की घोषणा की जिसमें कंपनियों की मांग के अनुसार राजस्व साझेदारी का मॉडल लागू कर दिया गया। निजी क्षेत्र की कंपनियों ने इस मॉडल का भरपूर फायदा उठाया और कई विदेशी कंपनियों के साथ इक्विटी भागीदारी कर मोटे मुनाफे कमाए। इस बीच पहले जो 26 प्रतिशत विदेशी निवेश

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंड से देखे तो दूरसंचार क्षेत्र देश में सबसे तेजी से बढ़ते शीर्ष पांच रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

को जो मंजूरी दी गई थी उसे बढ़ाकर शत प्रतिशत कर दिया गया।

अब निजी दूरसंचार कंपनियों को इस राजस्व हिस्सेदारी के मॉडल में भी परेशानी हो रही है। अब वे सकल राजस्व को नए सिरे से परिभाषित करने की मांग कर रही हैं और लगभग एक दशक से अधिक समय से कानूनी लड़ाई में उलझी हुई हैं। निजी कंपनियां सरकार के लिए राजस्व की गणना निवेश या संपत्ति की बिक्री या किराए से प्राप्त आय को बाहर करना चाहती है। जबकि पिछले साल अक्टूबर में अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की पुरानी व्याख्या को सही माना और निर्देश दिया है डीओटी की व्याख्या को बरकरार रखा जाए और इसी आधार पर निजी कंपनियों को भुगतान के लिए कहा जाए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिलायंस, टाटा और काफी हद तक एयरटेल ने भी मान लिया है लेकिन वोडाफोन आइडिया इसे मानने में अपनी लाचारी व्यक्त की है और खुद को दिवालिया घोषित करने की धमकी दी है। वोडाफोन आइडिया आदित्य बिड़ला समूह और यूके स्थित वोडाफोन के बीच एक संयुक्त उद्यम है।यदि वोडाफोन आइडिया भी दूरसंचार क्षेत्र से बाहर हो जाती है तो ऐसा करने वाली 10 बड़ी कंपनियों में वह शामिल हो जाती है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे दूरसंचार क्षेत्र कुछ खास कंपनियों का एकाधिकार स्थापित होने जा रहा है। अंदेशा इस बात का भी है एयरटेल भारती ने भी दूरसंचार छोड़ने का मन बना लिया है।

इस समय वोडाफोन आइडिया पर लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है। जिसमें 96,270 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम लाइसेंस के रूप में, 60,000 करोड़ रुपयेएजीआर बकाये के रूप में और 23,080 करोड़ रुपये का बैंक ऋण के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने बकायों के भुगतान के लिए निजी कंपनियों को 10 साल का समय दिया है।

यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि भारतीय दूरसंचार उद्योग दिन प्रति दिन आगे बढ़ रहा है और दूरसंचार कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। इस समय भारत में 116 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ता हैं। जीएसएम एसोसिएशन के अनुसार भारतीय मोबाइल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। 2019 में ही भारत ऐप डाउनलोड करने वाले में दुनिया का दूसरा सबसे देश बन गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंड से देखे तो यह क्षेत्र देश में सबसे तेजी से बढ़ते शीर्ष पांच रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

दूरसंचार क्षेत्र का सकल राजस्व मार्च 2021 की तिमाही में 68,228 करोड़ रुपये था। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2021 के दौरान इस क्षेत्र में कुल 37.66 बिलियन अमेरिकी डॉलरका निवेश हुआ। फिर भी यदि टेलीकॉम कंपनियां नकदी का रोना रो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी नीयत का भी सवाल है। कुछ लोग इसे टेलीकॉम सेवाओं की कीमत बढ़ाने के लिए मुहिम चलाने की बात कह रहे है तो कुछ खास हलकों में इसे सरकार को झुकाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। ❑❑

वायु प्रदूषणः अगर इच्छाएं द्रुतगामी होती...

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में सालाना लगभग 70 लाख लोग मारे जाते हैं। पिछले साल अकेले दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 57,000 मौतें हुई थीं। इसलिए लोगों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से छः प्रमुख प्रदूषकों के लिए अपने संशोधित वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा उन्हें और अधिक कठोर बना दिया गया है। लेकिन इन नए मानकों का मतलब है कि वैश्विक आबादी का 90 प्रतिशत और दक्षिण पूर्व एशिया की लगभग 100 प्रतिशत आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जो पहले (२००५) डब्ल्यूएचओ मानकों से 8 गुना अधिक है; यह नई (2021) सुरक्षित सीमा से 17 गुना अधिक होगा। दिशानिर्देश बताते हैं कि वायु प्रदूषक अब तक की तुलना में बहुत निचले स्तर पर हानिकारक हैं। छः प्रकार के खतरों में पार्टिकुलेट मैटर (2.5, 10), ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं। नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश (एक्यूजी) वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन प्रदान करते हैं, प्रमुख वायु प्रदूषकों के लिए नई सीमा निर्धारित करते हैं, और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कई कारकों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसमें शहरीकरण और आर्थिक विकास शामिल है, जो जीवाश्म ईंधन के जलने पर निर्भर करता है।

पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि वायु प्रदूषण न केवल एक स्वास्थ्य समस्या है, बल्कि आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 2020 में लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली को प्रति व्यक्ति आर्थिक नुकसान सबसे अधिक हुआ, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.08 प्रतिशत था। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कुल मौतों और बीमारियों को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 1.36 प्रतिशत के नुकसान से जोड़ा गया था।

डब्ल्यूएचओ वायु गुणवत्ता मानदंड विज्ञान पर आधारित हैं। वहीं राष्ट्रीय मानक, जिसकी जड़े वैज्ञानिकता की जगह राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी जरूरतों को संतुलित करने का प्रयास है। उदाहरण के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयास कुछ अन्य उद्देश्यों के साथ

पर्यावरण की सफाई का लक्ष्य वास्तव में सरकार की प्रशंसनीय पहल है, पर इसे लेकर कोई शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से इस मामले में गति बढ़ानी होगी, नही तो परिणाम 'जंगली हंस का पीछा' करने जैसा हो सकता है।
– केके श्रीवास्तव

सीधे संघर्ष में आते हैं, जैसे कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि हमारा उद्योग प्रतिस्पर्धी बना रहे, लागत निषेधात्मक न हो, उपभोक्ताओं को अत्यधिक भुगतान न करना पड़े, आदि। यही कारण है कि वायु गुणवत्ता पर्यावरण की दृष्टि से प्रगतिशील देशों में भी डब्ल्यूएचओ के मानदंडों से कम हैं। फिर भी खराब वायु गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य और उत्पादकता के बीच निर्णायक संबंधों के साथ, सरकारों के लिए अपने प्रयासों को तेज करना महत्वपूर्ण है। ये नए मानदंड भारत सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। नए मानक अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन नीति निर्माताओं को इसे अनदेखा न करने की सलाह दी जाएगी क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य को पहले की तुलना में प्रदूषण के निम्न स्तर से खतरा है। कड़े मानदंडों का मतलब है कि लगभग पूरा भारत वर्ष अधिकांश समय के लिए प्रदूषित क्षेत्र है।

भारत में अत्यधिक प्रदूषण वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन के अलावा भौगोलिक और मौसम संबंधी कारकों के कारण होता है। लेकिन स्वच्छ हवा के लिए भारत की खोज को भी नुकसान हुआ है क्योंकि यहां प्रदूषण प्रबंधन शायद ही कभी तदर्थ उपायों जैसे कि प्रतिबंध, जुर्माना या बिजली स्टेशनों को बंद करने से आगे निकल पाता है। एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है। इस खतरे से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ आने के लिए पर्यावरण वैज्ञानिकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, शहरी योजनाकारों, परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों आदि का कोई संयुक्त इनपुट नहीं है। इस तरह की ठोस कार्रवाई के अभाव में, वायु प्रदूषण को रोकने और बचाव का कोई भी कार्यक्रम, बस हवा हवाई ही होगा। सरकार खुद स्वीकार करती हैं कि अब तक केवल वृद्धिशील कदम

समस्या यह है कि हरित अर्थव्यवस्था में जाना महंगा है। वास्तव में हरित ऊर्जा स्रोतों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री - लिथियम आयन बैटरी और तांबे पर आधारित हरित विद्युतीकरण - स्वयं पर्यावरण नियमों के अधीन हैं और इसलिए उत्पादन करना महंगा है।

उठाए गए हैं। भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्य योजना खराब वायु गुणवत्ता के खतरों को पहचानती है। लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास नगण्य है और गति धीमी है। किसी भी मामले में, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में भारी कमी जैसे बड़े बदलाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा।

इसलिए भारत की वायु गुणवत्ता में कोई नाटकीय सुधार होने की संभावना नहीं है, भले ही एक ठोस प्रयास तुरंत शुरू किया गया हो। हवा की गुणवत्ता विभिन्न गतिविधियों पर निर्भर करती है और स्रोत पर ही इससे निपटने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि परिवेश गंदा है, या सड़कों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो कोई भी स्वच्छ हवा की उम्मीद नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में निर्माण एक बहुत ही अशुद्ध प्रक्रिया है। भारतीय सड़कें प्रदूषण को कम करने वाले बुनियादी मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं; सड़कें बहुत सारे हानिकारक कण छोड़ती हैं। स्वच्छ भारत, नमामि गंगा, उज्ज्वला योजना आदि जैसे कार्यक्रमों के जरिये सरकार प्रदूषण कम करने का दावा तो कर रही है, लेकिन यह दूर की कौड़ी है। इसका लाभ तुरंत मिलने वाला नहीं है।

प्रासंगिक सवाल यह है कि क्या एक्यूजी को लागू किया जा सकता है, खासकर भारत जैसे चुनौतीपूर्ण भू–जलवायु क्षेत्रों में। तुलनात्मक रूप से भारत का थ्रेशोल्ड स्तर कई गुना अधिक है। मुंबई अब मानकों से 8 गुना, कोलकाता 9.4 गुना और चेन्नई 5.4 गुना अधिक है। इस प्रकार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों और प्रदूषण शमन उपायों दोनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत को आर्थिक विकास लक्ष्य और प्रदूषण नियंत्रण उद्देश्य को संतुलित करने की आवश्यकता है। संक्षेप में कहें तो डब्ल्यूएचओ के मानक संभव नहीं लगते।

समस्या यह है कि हरित अर्थव्यवस्था में जाना महंगा है। वास्तव में हरित ऊर्जा स्रोतों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री – लिथियम आयन बैटरी और तांबे पर आधारित हरित विद्युतीकरण – स्वयं पर्यावरण नियमों के अधीन हैं और इसलिए उत्पादन करना महंगा है। बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति लागत निषेधात्मक है। दिन के अंत में, वायु प्रदूषण से लड़ना जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों का एक सबसेट है। समृद्ध दुनिया, जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक उत्सर्जन जिम्मेदारियों को वहन करती है, को विकासशील दुनिया को पर्याप्त प्रौद्योगिकी और वित्त हस्तांतरित करना चाहिए। भारत को अपनी ओर से अपनी बिजली, उद्योग और परिवहन क्षेत्रों को साफ करने, अंतरिम लक्ष्य निर्धारित करने और हवा को साफ करने के लिए एक अधिक सूक्ष्म क्षेत्रीय दृष्टिकोण की योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उपदेश देना आसान है, जबकि अभ्यास बाधाओं से भरा हुआ है।

(शेष पृष्ठ 24 पर)

शहरीकरणः एक एकीकृत रूप

विकास के नाम पर भौतिक संरचना, सामाजिक जटिलता और सामूहिक व्यवहार पर बगैर गौर किए देश में अंधाधुंध हो रहे अनियोजित शहरी विकास नागरिकों के समक्ष एक नई चुनौती का सबब बनता जा रहा है। आवश्यक बुनियादी ढ़ांचे के विकास और विस्तार के बगैर शहरीकरण का फैलाव रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं अधिक उत्पन्न कर रहा है, समाधान कम।

वर्ष 1925 तक भारतीय आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा गांव में निवास करता था, अब जबकि हमारी आबादी 135 करोड़ से ऊपर हो गई है, का एक तिहाई हिस्सा शहरों और कस्बों में रहने लगा है। 2036 तक यह संख्या बढ़कर 36 प्रतिशत हो जायेगी और सरकारी अध्ययन के मुताबिक 2046 में जब हम देश की आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे तो कुल आबादी का आधा हिस्सा यानि 50 प्रतिशत आबादी शहरीकृत हो जायेगी। चूंकि देश में कृषिगत गतिविधियां कम हो रही है इसलिए रोजी–रोजगार के लिए लोगों का पलायन हो रहा है और उसी रफ्तार में शहरीकरण बढ़ रहा है। वर्तमान में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रमुख रूप से शहरी है। सन् 2036 तक ऐसे राज्यों की संख्या बढ़कर 18 होने वाली है। 1970 में भारत में 50 लाख से अधिक लोगों के लिए सिर्फ दो शहरी समूह थे, आज बढ़कर 9 हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा शहरी फैलाव वाला ठिकाना बन जाएगा।

समाजशास्त्र की भाषा में किसी भी समाज का शहरीकरण सुसंस्कृत रूप में स्वीकार किया जाता है। हमारे यहां उल्टा है। क्योंकि अपर्याप्त टूटे–फूटे बुनियादी ढ़ांचे (बिजली, सड़क, पानी) तथा कई बार खतरनाक जोखिम के साथ बगैर दूरगामी परिणामों के अध्ययन के शहरी विकास का क्रम जारी है। इसी बेतरतीब बढ़ोतरी के चलते सामाजिक, आर्थिक अथवा धार्मिक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच विषमता भी बढ़ी है। कई बार सामाजिक या धार्मिक आधार पर विरोध के भी स्वर उभरते रहे हैं। जिन शहरों में अनियोजित फैलाव हो रहा है, वहां बिजली साझा करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक ग्रिड नहीं है, कुशल परिवहन

शहरी नियोजन केवल भौतिक रूप के कुशल ढ़ांचे को खड़ा करना नहीं है बल्कि इसकी नींव प्रभावी सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण में भी निहित है, इसलिए शहरी योजनाकारों को तीनों आयामों को ध्यान में रखना होगा।

– डॉ. जया कक्कड़

नेटवर्क नहीं है, जल आपूर्ति या जल निकासी का कोई मॉडल नहीं है। इस तरह की भिन्न–भिन्न समस्याएं हैं, लेकिन समाधान या तो है ही नहीं या है भी तो उल्टा–पुल्टा या 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसा है। जैसे– सड़क पर भीड़ कम करने के लिए सम–विषम योजना या पार्किंग चार्ज में ऊंची वृद्धि। दरअसल शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सभी बुनियादी ढ़ाचे को एकीकृत करने की आवश्यकता है और सामूहिक जीवन को नियोजन के दौरान सबसे ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए आवास, परिवहन, बिजली, पानी के साथ जलवायु से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की जरूरत है, क्योंकि 2030 तक भारत की शहरी आबादी 65 करोड़ के आस–पास होगी और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 70 प्रतिशत योगदान यहीं से होगा। वर्तमान में आधे से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है लेकिन इनका योगदान केवल 18 प्रतिशत है।

हालाँकि, शहरी नियोजन को एक आर्थिक मुद्दे के रूप में देखने का अर्थ यह है कि शहरी क्षेत्रों का विकास कैसे होना चाहिए, इसका एक बहुत ही अदूरदर्शी दृष्टिकोण है। वास्तव में शहरी स्थान गतिशील संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरण और भू–स्थानिक विचारों के संयोजन से आकार लेती हैं। इस प्रकार प्रत्येक शहरी क्षेत्र अपनी जरूरतों और विकास की आकांक्षाओं के साथ अद्वितीय है। दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत संरचना सौंपी जिसे हमारे संविधान ने और मजबूत किया। इस योजना के तहत स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना एक पक्ष के रूप में देखा जाता है न कि एक वैध अधिकार के रूप में। शहरों पर या तो नौकरशाहों का शासन होता है जिनके पास लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है या स्थानीय प्रतिनिधियों के पास सीमित शक्ति होती है। हमारे लोकतंत्र ने उन राज्यों के लिए स्थानीय सरकारों के साथ बॉटम–अप दृष्टिकोण का पालन नहीं किया, जो संविधान बनाते समय प्रमुखता से चिन्हित किया गया था। शासन का यह विरासत में मिला मॉडल केंद्रीकृत हुक्मरान को मजबूत करता है और स्थानीय नियोजन के लिए प्रतिकूल है जो उस क्षेत्र की जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है।

शहरी नियोजन को एक आर्थिक मुद्दे के रूप में देखने का अर्थ यह है कि शहरी क्षेत्रों का विकास कैसे होना चाहिए, इसका एक बहुत ही अदूरदर्शी दृष्टिकोण है। वास्तव में शहरी स्थान गतिशील संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरण और भू-स्थानिक विचारों के संयोजन से आकार लेती हैं।

शहरी चुनौतियां केवल स्वच्छ, हरित और बेहतर भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए बेहतर योजना में तब्दील नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन यह शहरी विकास के बारे में एक बहुत ही अदूरदर्शी दृष्टिकोण है। सभी शहरी स्थानों में ऐसे लोग रहते हैं जो एक ही समय में विषमता और एकरूपता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में खुद को बनाए रखते हैं। यह आवश्यक है कि सभी हितधारकों को एक साथ लाया जाए ताकि जलवायु को आगे प्रकृति आधारित और (सामाजिक और आर्थिक रूप से) समावेशी शहरी स्थान के रूप में बढ़ाया जा सके। जिस चीज की जरूरत है वह है सहयोग की, टकराव की नहीं। उदाहरण के लिए, किसी भी प्रस्तावित विकास से किसी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक तरफ राष्ट्रीय और निर्मित पर्यावरण और दूसरी तरफ निवासियों की जरूरतों और आकांक्षाओं के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन होना चाहिए। हमेशा की तरह हमारा गौरवशाली अतीत हमें सीखने के लिए सबक प्रदान करता है।

बार–बार दोहराया जाता रहा है कि शहरी जीवन एक मिश्रित जीवन शैलियों का समूह है जिनमें काम के बेहतर अवसर वस्तुओं या संस्कारों के विनिमय तथा बेहतर नागरिक सुविधाओं जैसी चीजें विशेषाधिकार की तरह शामिल है। लेकिन अनियोजित शहरीकरण के कारण लोग छोटे–छोटे दड़बों में रहने के लिए बाध्य है, खुले स्थानों पार्क, खेल के मैदान आदि की कमी है, खुले में शौच से भी पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है और रोजी–रोटी की भागदौड़ में सामाजिक एकता की भी कमी बनी हुई है। अमरीका समाजशास्त्री लुई विर्थ के अनुसार भौतिक संरचना, सामाजिक संगठन और सामुहिक व्यवहार एक–दूसरे को प्रभावित करते है। शहरी जनसंख्या एक निश्चित स्थान तक सीमित होती है, जिसमें छोट–छोटे परिवार और छोटे कार्यसमूह होते है, जिसे हम कई बार आर्थिक अथवा व्यवसायिक आधार पर पहचान रखते है। प्रत्येक शहरी निवासी से एक सामुहिक व्यवहार की संहिता का पालन करने की उम्मीद की जाती है, भले ही वह उसे पसंद हो या ना पसंद हो।

क्योंकि वह उस शहर विशेष की विशेष पहचान से जुड़ी है। उदाहरण के लिए– दिल्ली, मुंबई, कोलकता और चैन्नई की तुलना करें तो हम सहज ही यह कह सकते है कि इन सभी शहरों में एक सामान्य बात है कि ये सभी शहर गैर कृषि बस्तियों वाले है, लेकिन फिर भी इन शहरों की अपनी एक अनूठी सामूहिक संस्कृति भी है। शहरीकरण से उस मूल संस्कृति को नुकसान होने के कारण ही सामाजिक एकता का भाव कम होता जा रहा है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत नगरवाद की अवधारणा से अपरिचित नहीं है। हमारे प्राचीन अतीत से शुरू होकर अंग्रेजों के देश में आने तक शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ है। इन स्थानों का अध्ययन आज के समय में शहर और देश के योजनाकारों के लिए महत्वपूर्ण सबक है। हम अपने मामले को चुनिंदा उदाहरणों की मदद से आसानी से समझ सकते है।

मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से लगभग 5 किमी दूर स्थित था। इसलिए यह व्यापार और विनिमय के लिए एक आदर्श स्थल बन गया। इसके अलावा, इसका समर्थन करने के लिए कृषि के साथ एक समृद्ध आंतरिक भूमि थी। उस समय के पुरातात्विक अवशेषों के प्रमाण के रूप में इसमें भौतिक समृद्धि थी। सामाजिक संगठन को बस्तियों के रूप में देखा जाता है जिन्हें श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया था। समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक जटिलता थी। शहर ने निर्माण और प्रशासनिक केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में, शहर ने कई कारकों पर खुद को कायम रखा। अपशिष्ट जल को प्रवाहित करने के लिए नलिकाओं वाली अच्छी सड़कें थीं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने वाले लगभग 700 कुएं थे। इस प्रकार शहर तीन आयामों – भौतिक संरचना, सामाजिक जटिलता और सामूहिक व्यवहार के अनुरूप था।

दूसरी ओर, फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा सभी भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ बनाया गया था। एक कृत्रिम झील के निर्माण के बावजूद, पानी की आपूर्ति अपर्याप्त साबित हुई। शहर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग नहीं बन सका। संक्षेप में, एक समृद्ध और पूर्ण जीवन पाने के लिए आपको टिकाऊ कारकों के एक विविध सेट की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, भौतिक संरचना उनमें से एक है। एक शहर को समय की चुनौतियों का हल ढूंढने की जरूरत है।

मुगल साम्राज्य की राजधानी शाहजहानाबाद में उत्कृष्ट नगर नियोजन था। यह लाभकारी रूप से बारहमासी नदी यमुना के किनारे पर स्थित था, जिससे पानी की प्रचुर आपूर्ति और व्यापार मार्गों की आवाजाही थी। इसके पास एक विशाल कृषि क्षेत्र था। दीवारों की परिधि, सुनियोजित सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, यहां तक कि अस्पताल और मदरसा के कारण इसका एक सीमित क्षेत्र था। धीरे–धीरे कई अन्य इलाके और सार्वजनिक स्थान जैसे विभिन्न अनुनय के पूजा स्थल, मनोरंजन के स्थान आदि सामने आए। दूसरे शब्दों में, शहर आवास, आत्मसात, अवशोषण, संघर्ष, समाधान और संवाद की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाने के कारण विकसित हुआ। उदाहरण के लिए, रिक्त स्थान, सामाजिक संपर्क को तीव्र करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। राज्य रिक्त स्थान को श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में अलग करने से दूर रहा। एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान समय के साथ विकसित हुई। शहर की पहचान सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के साथ हुई – साहित्य कविता, संगीत, नृत्य, सार्टोरियल शैली और व्यंजन। सांस्कृतिक अंतरंगता हावी होने के दौरान धार्मिक विविधता पर मोह नहीं था। शहर ने बढ़ती आबादी, विविध सामाजिक, धार्मिक, जातीय, और अपने निवासियों के व्यावसायिक प्रोफाइल और उनकी कई आकांक्षाओं की चुनौतियों पर बातचीत की और प्रचलित शहरी स्थानों के भीतर सामाजिक और स्थानिक पदानुक्रम बनाने के लिए सामाजिक बातचीत पर जोर दिया।

मोटे तौर पर ग्रामीण इलाकों से जो लोग शहरों में जाते हैं वे विविध पृष्ठभूमि वाले होते हैं, अपने साथ वे जिन इलाकों से चलकर आए होते है, वहां की आदतें, शौक और संस्कृति भी लाते हैं, लेकिन शहर में एक सीमित जगह में बिल्कुल नए वातावरण में रहने लगते है। गांव से शहरों की और होने वाली आवाजाही जल्दी ही उन्हें सांस्कृतिक अलगाव तथा बेमेल रहन–सहन, खान–पान के लिए बाध्य करने लगती हैं। हालांकि इस तरह की विषमता साझा स्थानों, संसाधनों, समारोहो, परिवहन आदि जैसे स्थानों पर सीधे दिखती है, लेकिन समय के साथ इसे ठीक किया जाता रहा है। कई बार भाषा या वेशभूषा के जुड़ाव के भी ऐसे छोटे–मोटे मतभेदों पर एकजुटता बनने लगती है। समस्या आर्थिक जटिलताओं को लेकर होती है। सामाजिक जटिलताओं को संभालने के लिए भौतिक पहलूओं की बेहतरीन रूपरेखा तैयार की जाए तो चीजे संभल सकती है।। दूसरों के लिए सहानुभुति या इसके विपरीत सवामित्व की सामूहिक भावना भी कारगर होती है जो सामूहिक व्यवहार द्वारा पोषित होती है जिसमें संघर्ष की कम संभावना होती है। आशय यह है कि शहरी नियोजन केवल भौतिक रूप के कुशल ढ़ांचे को खड़ा करना नहीं है बल्कि इसकी नींव प्रभावी सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण में भी निहित है, इसलिए शहरी योजनाकारों को तीनों आयामों को ध्यान में रखना होगा। ❑❑

मुद्रीकरण योजना- खजाना ढूँढने का प्रयास

महाभारत में एक कथा आती है कि व्यास ऋषि और कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने युद्ध के कारण तिजोरी खाली होने की बात कही तो कृष्ण भगवान ने उन्हें मेरु पर्वत के पास खुदाई से सोना निकालने की सूचना दी। युधिष्ठिर ने उनके कहे अनुसार खुदाई की और सोना निकालकर अश्वमेध यज्ञ किया। आज सरकार की स्थिति भी युधिष्ठिर जैसी है। कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियां धीरे हुई है और अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ी है। लेकिन सोना कहा मिलेगा, यह बताने के लिए अब कृष्ण भगवान नहीं है। हाँ आज हर जगह पर अर्थशास्त्री मौजूद है जो गलत–सलत सलाह देते रहते है। सरकार को भी देश चलाना है और विकास भी करना है। खजाने की खोज तो करनी ही पड़ेगी। सार्वजनिक संपातियों का मुद्रीकरण एक ऐसे ही खजाना खोजने की योजना है। इससे कितना खजाना मिलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

क्या है यह मुद्रीकरण योजना

सरकार बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन पैसे की कमी है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और उसके बगैर आर्थिक विकास नहीं हो सकता। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र इसमें आगे आए और इसका भार संभाले। पहले भी कई कोशिशें हुई, लेकिन फायदे की गारंटी के बगैर कोई ज्यादा सामने नहीं आया। अब सरकार चाहती है कि सार्वजनिक संपतियों का उपयोग करके 'बनाओ और कमाओ' के तहत निजी क्षेत्र काम करें। खुद भी कमाए और सरकार को भी कुछ कमाई का हिस्सा दे। इसको ही सरकार सार्वजनिक संपाति का मुद्रीकरण कह रही है। सरकार के कहे अनुसार पाँच वर्षों में (2020–25) इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 111 लाख करोड़ रूपये लगेंगे। उसमें से 85 प्रतिशत तो बैंक और ऐसे ही साधनों से आयेगा। 5–6 प्रतिशत पैसा मुद्रीकरण करके लाना पड़ेगा। वही सरकार करने जा रही है।

सरकार ने तय किया है कि मुद्रीकरण मूल्य तय करने हेतु जहाँ तक हो सके बाजार का आधार लिया जाये और जहाँ वह गुंजाइश नहीं है वहाँ दूसरे तरीके अपनाए जाये। बहराल इसमें सरकार खुले मन से जाना चाहती है और समयानुसार मुद्रीकरण मूल्य तय करना चाहती है।

– अनिल जवलेकर

सरकार क्या करने जा रही है

सभी रास्ते, पॉट्र्स, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, जहाज टर्मिनल, रेलवे ट्रक, रेलवे कॉलोनी, बिजली निर्माण और हस्तांतरण, गैस पाइप लाइन, स्टेडियम, गोदाम, टेलीकोम टावर और फाइबर, खदान वगैरह जैसी कई इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सार्वजनिक संपतिया सरकार निजी क्षेत्र को देकर विकसित करना चाहती है और पैसा भी वसूलना चाहती है। आने वाले चार सालों में 6 लाख रुपये जमा करने का सरकार का इरादा है। सरकार चाहती है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र जितनी भी पूंजी लगाने को तैयार है, उसे ही मुद्रीकरण मान लिया जाए। सरकार ने तय किया है कि मुद्रीकरण मूल्य तय करने हेतु जहाँ तक हो सके बाजार का आधार लिया जाये और जहाँ वह गुंजाइश नहीं है वहाँ दूसरे तरीके अपनाए जाये। बहराल इसमें सरकार खुले मन से जाना चाहती है और समयानुसार मुद्रीकरण मूल्य तय करना चाहती है।

इसका क्या मतलब है

यह स्पष्ट है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और निजी क्षेत्र के भरोसे सरकार विकास करना चाहती है और उसके लिए अपने अधिकार में आने वाली सार्वजनिक संपतियों का उपयोग करना चाहती है। इसका एक मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि सेवा का उपयोग करने वाले नागरिक सीधे ऐसी योजनाओं का खर्चा उठाए। निजी क्षेत्र जो भी सेवा देगा उसकी वसूली उपभोग कर्त्ता से करेगा। इससे सरकार टैक्स लगाने से बच सकती है। वैसे यह बात छुपी नहीं है कि सरकार घाटे में चलती है और अपना ही खर्चा नहीं उठा पाती तो विकास कैसे करेगी। दूसरा मतलब है कि सरकार आजकल आर्थिक योजनाओं के बदले गरीबों को प्रत्यक्ष लाभ देने वाली कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है ताकि गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से मदद कर सके। इसका तीसरा मतलब यह भी है कि अब आर्थिक क्षेत्र में निजी कंपनियों का बोल–बाला रहेगा और सरकार का हिस्सा कम होता जाएगा।

निजी क्षेत्र का अपना महत्व है

यह कहने की जरूरत नहीं है कि निजी क्षेत्र का अपना महत्व है और आर्थिक विकास में उसका सहयोग जरूरी है। निजी क्षेत्र को कम करके आंकने की मानसिकता से देश बाहर आया है और 1990 के दशक से ही निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में निजी क्षेत्र ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। सार्वजनिक सुविधाओं का विकास और रखरखाव एक संवेदनशील विषय है और यह विकास मुनाफे का नहीं होता। इसलिए सार्वजनिक कहे जाने वाले उद्योग के विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग मर्यादित रहेगा, यह बात समझनी होगी।

सरकार को ज़िम्मेदारी नहीं भुलानी चाहिए

सवाल यह नहीं है कि निजी क्षेत्र का विकास में महत्व है कि नहीं। सवाल यह है कि सरकार का विकास के प्रति क्या दायित्व है? इसको नकारा नहीं जा सकता कि सरकार का मुख्य दायित्व सार्वजनिक संपातियों को संभालकर रखना और उसका सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में लाना है न कि उसको निजी क्षेत्र या कंपनियों को उनके फायदे के लिए किराए पर देना है। यह सभी जानते है कि निजी क्षेत्र अपने फायदे के लिए काम करता है न कि सार्वजनिक हित के लिए। इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी नजर ऐसी सार्वजनिक संपातियों पर होती है जो कभी उनकी हो सकती है। सरकार भले ही यह कह रही हो कि वो संपात्तियों को बेच नहीं रही है और सभी मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेंगे। लेकिन यह नहीं भुला जा सकता कि सरकारें बदलती है और सरकारों की विचारधाराएं भी बदलती है। कल हो सकता है कि सरकार मालिकाना हक भी बेच दे। तब आज सस्ते में ली हुयी संपात्ति अनायास ही निजी क्षेत्र को मिल जाएंगी और वह बात सार्वजनिक हित में नहीं है। उसी तरह निजी क्षेत्र को विकास काम करने देने का मतलब दुहरी टैक्स पद्धति अपनाने जैसा है क्योंकि निजी क्षेत्र अपना खर्चा उपभोगकर्त्ता से लेगा और सरकार भी अपना कोई टैक्स कम नहीं करेगी। जनता का बोझ तो बढ़ना तय है और यह अच्छी नीति नहीं कही जा सकती।

क्या खजाना मिल पाएगा

भारत में निजी क्षेत्र को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में शामिल करने या सार्वजनिक उद्योग निजी क्षेत्र के हवाले करने की बाते पहले भी हो चुकी है और उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब भी बहुत कुछ होगा ऐसा नहीं कह सकते। निजी क्षेत्र को सिर्फ फायदे की बात समझ आती है और जब तक फायदे की गारंटी नहीं मिलती वह ऐसे कामों के लिए सामने नहीं आते। और दूसरी बात सार्वजनिक सम्पत्ति की अलग–अलग तरीके से किराए की बात शायद हकीकत में लाना मुश्किल होगा। पेसेंजर ट्रेन कोई और चलाएगा और स्टेशन कोई और बनवाएगा कहना मुश्किल है। हाँ यह हो सकता है कि कुछ बड़ी कंपनियाँ, जिसमें विदेशी कंपनियाँ भी शामिल है, बहुत सारी सार्वजनिक संपत्तियों को विकास के नाम पर अपने नियंत्रण में लेगी। इसलिए यह देखना होगा कि इस तरह के मुद्रीकरण से कितना कुछ खजाना मिलेगा। कल्पना में मुद्रीकरण जितना अच्छा लगता है शायद उतना हकीकत में उतरेगा इसे लेकर शंका तो रहेगी ही। ❑❑

शहरी विकास के लिए खेती से खिलवाड़

वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन के वजूद में आने के कुछ दिन बाद, मुझे लंदन के 'द इकोलॉजिस्ट' ने भारतीय और यूरोपियन किसान के बीच तुलनात्मक लेख लिखने को आमंत्रित किया था। इसके पीछे मंशा यह जानने की थी कि भारत के खेतों में फसल उगाने के लिए होने वाला खर्च क्योंकि अपेक्षाकृत कम है तो क्या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकल्प खुलने का कोई आर्थिक लाभ हुआ है। यह वह आम धारणा है, जिसे मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों ने, किसानों के विरोध के बावजूद, व्यापार संधि पर हस्ताक्षर को न्यायोचित बताने के लिए तैयार किया था। उनमें एक तर्क तो विश्व व्यापार संगठन की इस संधि को किसानों के लिए बड़ा 'धमाकेदार मौका' बताने तक चला गया। इस उम्मीद के साथ कि कृषि उत्पाद के निर्यात में बहुत बड़ा उछाल आएगा, किसान की आमदनी बढ़ने का कयास लगाया था, जिससे भारतीय कृषि की सूरत में बदलाव आना तय माना गया था। लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सुबूत उपलब्ध न होने के कारण और बताए जा रहे कथित फायदों के नदारद होने पर, वास्तव में मैंने भारतीय किसान की तुलना यूरोपियन नस्ल की गाय से की थी।

विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के लगभग 26 साल बीतने के बाद, कृषि और ग्रामीण भारत पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की पिछले हफ्ते आई नवीनतम रिपोर्ट में जो मंज़र सामने आया है, वह सोचनीय है। यह वस्तुस्थिति आकलन अध्ययन वर्ष 2018–19 में हुआ था। सर्वे रिपोर्ट में आय के हिसाब से किसान और गाय लगभग एक से हैं, लेकिन जो कुछ सामने आया है वह भयावह है – एक औसत भारतीय किसान की कमाई खेत–मजदूर से भी कम है। यदि आजादी के 75 साल बाद भी किसानों की आमदनी अपने खेतों में काम करने वाले मजदूर से कम है, तो यह केवल यही दिखाता है कि जानबूझ कर बनाई गई आर्थिक नीतियों का मंतव्य कृषक की आमदनी इतनी कम रखना है कि मजबूरन खेती छोड़ शहरों की ओर पलायन करे, क्योंकि वहां सस्ते मजदूरों की जरूरत है, और बरसों से यही लीक चल रही है।

विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के लगभग 26 साल बीतने के बाद, कृषि और ग्रामीण भारत पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की पिछले हफ्ते आई नवीनतम रिपोर्ट में जो मंज़र सामने आया है, वह सोचनीय है।

– देविंदर शर्मा

वर्ष 2012–13 में जब आखिरी वस्तुस्थिति आकलन अध्ययन हुआ था, तब एक कृषक परिवार की आमदनी कुल उपज की लगभग 48 फीसदी थी, जो वर्ष 2018–19 आते–आते 38 प्रतिशत से नीचे चली गई। जबकि इसी अवधि में केवल खेत–मजदूर के वेतन का हिस्सा

32 फीसदी से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। औसत कृषक परिवार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वेतन देने में निकल जाता है, और उम्मीद है आने वाले सालों में भी यह चलन बना रहेगा। 'कुल किये गए भुगतान' के आधार पर की गणना के मुताबिक एक किसान परिवार की कुल मासिक आय 10,218 रुपये बैठती है। यदि इसकी तुलना वर्ष 2012–13 में रही आय यानी 6426 रुपये से करते हुए और मुद्रास्फीति जोड़ने के बाद इसमें 16 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी हुई है। 'किये गए भुगतान' और अन्य अवयवों को शामिल करने के बाद वर्ष 2018–19 में किसान की औसत मासिक आय 8337 रुपये बनती है। इस अन्य अवयवों का मतलब है– खेती करने में घर खर्च से डाला गया पैसा, बकाया मजदूरी, मशीनरी, बीज इत्यादि पर पल्ले से किया खर्च। तथापि जहां तक फसल उगाने की बात है, एक औसत कृषक परिवार की वर्ष 2018–19 में मासिक आय 3,798 रुपये रही थी। अब वास्तव में, जब इसमें मुद्रास्फीति को भी जोड़ें तो 2012–13 से 2018–19 के बीच आय में दरअसल 8.8 प्रतिशत की कमी हुई है। इसको आगे यदि दिहाड़ी के हिसाब से बताया जाए, जैसा कि एक अखबार में छपा हैरान करने वाला विश्लेषण बताता है, तो खेती से हुई रोजाना आय मात्र 27 रुपये बैठती है! यहां तक कि मनरेगा में काम करने वाला मजदूर इससे ज्यादा दिहाड़ी बना लेता है। इससे केवल वही निष्कर्ष निकलता है, जो मैं सालों से कहता आया हूं ''किसान को मिल रही भोजन पैदा करने की सजा। किसी भी सूरत में, खेती से होने वाली रोजाना आय एक दुधारू गाय से होने वाली आय से भी कम है, क्योंकि डेयरी से निकलने वाले एक लीटर दूध की थोक कीमत लगभग 30 रुपये है।

जितनी कृषि–आय कम होगी उतना

किसान के सिर चढ़ा औसत कर्ज, जो वर्ष 2012–13 में 47,000 था वह 2018–19 में बढ़कर 74,100 रुपये हो गया। भारत के कुल किसानों पर लगभग 50.2 प्रतिशत सिर पर कर्ज बकाया है।

ही आगे कर्ज लेने में मुश्किल पेश आएगी। कई बार विभिन्न स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है। किसान के सिर चढ़ा औसत कर्ज, जो वर्ष 2012–13 में 47,000 था वह 2018–19 में बढ़कर 74,100 रुपये हो गया। भारत के कुल किसानों का लगभग आधा यानी 50.2 प्रतिशत के सिर पर कर्ज बकाया है। हैरानी की बात है कि मिजोरम में बकाया ऋण में भारी–भरकम 709 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, इसके बाद सूची में उत्तर–पूरब से असम और त्रिपुरा का स्थान है।

हाल ही में, मार्च, 2021 के अंत में, संसद को बताया गया है कि किसानों की तरफ रहता कुल बकाया ऋण 16.8 करोड़ है, सूची में सबसे ऊपर तमिलनाडु है। यह देखते हुए कि भारत में लगभग 77 फीसदी परिवार खेती आधारित स्व–रोजगार वाले हैं और इनमें 70.8 फीसदी के पास 1 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि है। 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसानों की गिनती केवल 9.9 प्रतिशत है। परिवार की कृषि से होने वाली आय वह मानी जाती है, जहां एक घर में 4,000 रुपये से ऊपर की आमदनी खेती और अन्य संबंधित गतिविधियों से हुई हो, और घर का कम से कम एक सदस्य साल भर शुद्ध रूप से किसानी करता हो। अब देशभर में चूंकि 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान महज 0.2 प्रतिशत हैं, तो यह तथ्य उस भ्रामक प्रचार की हवा निकालने को काफी है, जिसमें कहा जा रहा है कि मौजूदा किसान आंदोलन वस्तुतः बड़े किसानों द्वारा चलाया जा रहा है।

किसान छोटा हो या बड़ा, उसको हक से बनती कमाई से महरूम रखना उस कुटिल नीति के तहत है जिसे पिछले कुछ दशकों में एक–के–बाद–एक बनी केंद्रीय सरकारों ने आगे बढ़ाने का काम किया है ताकि लोगों को खेती से हटाया जाए। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी संस्थाएं चाहती हैं कि ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करे, ऐसा करना उस बलवती आर्थिक सोच के तहत है कि शहरी जनसंख्या की गति बढ़ने से तेज आर्थिक विकास स्वतः बनता है, खेती के तौर–तरीकों को जानबूझ कर पुरानी लीक पर कायम रखने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसान खुद से खेती से तौबा कर पलायन करने को मजबूर हो जाए। हैरानी नहीं होगी यदि वस्तुस्थिति आकलन सर्वे की रिपोर्ट 2018–19 को मुख्यधारा के अर्थशास्त्री आधार बनाकर शहरों की ओर पलायन वाली योजना में और तेजी लाने के लिए कहने लगें। जबकि होना उलटा चाहिए।

जहां भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने वर्ष 2020–21 में रिकॉर्ड 30.86 करोड़ मीट्रिक टन का आंकड़ा छुआ है, साल–दर–साल उपज बढ़ी है, इसके विपरीत खेती से होने वाली आय नीचे की ओर जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) द्वारा पिछले 20 सालों (2002–21) पर तैयार प्रॉड्यूसर सब्सिडी एस्टीमेट हमें बताता है कि वियतनाम, अर्जेंटाइना और भारत, ऐसे तीन देश हैं जो अपने किसानों पर नेगेटिव टैक्स लगा रहे हैं। कुल कृषि आय के आधार पर भारत ने अपने किसानों पर लगभग माइनस 5 फीसदी कम कर टैक्स लगा रखा है। ❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/annadata-at-the-mercy-of-the-creator-64238/

लोकतंत्र और आम आदमी की जागरुकता

जब से भारत मुगलों व अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ तभी से देश में क्षीण हुई लोकतंत्र की धारणा बलबती होती चली आ रही है फिर संविधान लागू हो जाने के बाद राजनीति के क्षेत्र में देश के आम आदमी को महत्वपूर्ण बना दिया गया परन्तु कालान्तर में देश के राजनेताओं ने आम आदमी को केवल वोट समझा तथा उसकी याद केवल चुनाव के समय व मतदान के दौरान ही आती रही। यदि देश का प्रधानमंत्री देश की जनता से लोकतंत्र के वोट पर्व में अधिक से अधिक तादाद में भाग लेने का आवाहन करता है तो देश के कुछ चिरविरोधी राजनेताओं को इसमें भी राजनीति नजर आती है।

एक समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर भाास्त्री ने देश के आम लोगों से आवाहन किया था कि देशवासी कुछ दिनों के लिए एक वक्त का भोजन छोड़ दें ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही भुखमरी की समस्या से कुछ सीमा तक छुटकारा मिल सके। उस समय किसानों की हालत खराब हो गयी थी तथा फसलों को काफी नुकसान पंहुचा था। देश की जनता ने लालबहादुर भाास्त्री की बात मानी और देश खाद्यान्न सकंट से कुछ सीमा तक मुक्ति प्राप्त कर सका था। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने आवाहन किया था कि भारत में बिखरे हुए लोग आज के भारत में एक होकर रहे तो जनता ने गांधी जी का साथ दिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने युवाओं से आवाहन किया था तो युवा उनके साथ आंदोलन में एक साथ हो गये। भारत में कुछ नेता ऐसे भी हुए है जिनकी एक आवाज पर जनसैलाब उमड़ पड़ता है तथा जनता भागी–भागी उनके भाषण सुनने के लिए चली आती है। परन्तु ऐसा तभी होता है जब जनता के दिल में राजनेता के प्रति ईमानदारी व निरपेक्षता की छवि होती है और उस राजनेता का आहवान देश के हित में होता हो।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा सफाई अभियान व स्वच्छता अभियान में अपने मन्त्रियों व आम आदमी का आवाहन किया तो बड़े बड़े उद्योगपतियों व अभिनेताओं सहित आम आदमी ने हाथ में झाड़ू उठा ली तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा घोषित नौ रत्नों ने सफाई के अभियान का शुभारम्भ किया। परन्तु एक सर्वे के अनुसार स्वंय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चुनावी क्षेत्र बनारस को देश के सबसे गंदे शहर की सूची में शामिल पाया। जब

आम आदमी देश की स्वतंत्रता प्राप्त करते समय भी जागरुक था और आज भी जागरुक है। उसकी इसी जागरुकता के कारण लोकतंत्र भारत में सुरक्षित है।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

कोई नेता देश के नवयुवको का आवाहन करता है तो देश में नवसंचार होता है। जोश और नयी उम्मीद व नई दिशा का संचार नवयुवकों में होता है। नेतृत्व यदि ठीक है तो दिशा भी सही होगी उसमें भटकाव कम होगा।

आम आदमी आज टीवी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से आसानी से सही व गलत का आकलन कर लेता है। अब वह जमाना नहीं कि देश के नेता की झलक पाने के लिए लोग बड़ी तादाद में सिर्फ उसको देखने के लिए ही आते थे। समाचार दूरदर्शन व ऑल इंड़िया रेड़ियो पर ही निश्चित समय पर समाचार आने की प्रतिक्षा रहती थी। अब टी वी के कई चैनलों पर 24 घंटे समाचारों को सुनाते व दिखाया जाता है। अब राजनेता व अन्य लोग ऐसे हथकंड़े अपनाते है कि मीड़िया बाध्य होकर उनको दिखाता है और ऐसे राजनेता व लोग पब्लिसिटी प्राप्त कर लेते है तथा बेवजह की बहस चैनलों पर शुरु हो जाती है।

अब देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय नई दिल्ली में कन्हैया जैसे छात्र देश को तोड़ने के नारे लगाते हुए लोकप्रिय होकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के दिलों में स्थान प्राप्त कर लेते है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी उनको ससम्मान अपनी पार्टी में स्थान भी दे देती है। कैम्पस में कन्हैया की लोकप्रियता रातों रात हो जाती है। भुखमरी, साम्यवाद से आजादी की मांग करते करते ऐसे छात्र सही गलत का एहसास भी भूल जाते है। आजादी पंसद ऐसे छात्र दिल्ली व उससे सटे हुए क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए कभी भी कोई आंदोलन व प्रदर्शन नही चलाते। प्रधानमंत्री अगर देशवासियों से अधिक से अधिक वोट ड़ालने का आवाहन करते है तो इसमें परेशानी क्या होनी वाहिए परन्तु अखिलेश जैसा राजनेता पीएम बदलने के लिए वोट करने की अपील कर अपनी मानसिकता ही दिखाते है।

लगभग एक दशक के राजनीतिक परिदृश्य में देश के राजेनता विषम परिस्थितियों में जुबानी संयम खो रहे है। एक दो दशक पूर्व तक चुनावों में छोटे से बड़े राजनेता भाषण देते थे पर कोई भी किसी विपक्षी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता था।

जो भीड़ आज एक नेता के जुलूस में होती है वही लोग दूसरे दिन किसी अन्य राजनेता के लिए नारे लगा रही होती है। गरीबी व भुखमरी से जूझते लोग अपने विवेक का प्रयोग किये बिना अंधानुकरण करते हुए मात्र एक दिन के नाश्ते व खाने के लिए किसी भी राजनेता का समर्थन करने चल देते है। लोग जिनके ऊपर परिवार के भरणपोषण की जिम्मेदारी होती है तथा आर्थिक तंगी होती है जिससे उनका विवेक नष्ट हो जाता है और वे विवेक से परे देश के भविष्य की नहीं सोच कर वे मात्र जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि में ही रोजगार प्राप्त करने लगते है। महीनों–महीनों चलने वाले धरने में ऐसे लोगों की बाहुल्यता होती है। उन्हें सरकार के द्वारा कही गई बातों से कोई मतलब नही होता है वे तो यह चाहते रहते है कि वर्तमान धरना प्रदर्शन लम्बा चलता रहे और उन्हें प्रतिदिन खाना, पीना व मजदूरी मिलती रहे तथा उत्पादन कार्य करने से बचते रहे। इसलिए ऐसे आम आदमियों को किसी भी नारे लगाने से कोई परहेज नहीं होता है, वे तो इंतजार करते है कि कब उन्हें मजदूरी व खानाखुराक व दारु मिले और उन्हें प्रदर्शन व धरने में जाने का आदेश अपने ठेकेदार से मिले। वे निरन्तर पूछते रहते कि कल कहां जाना है। अब राजनीतिक पार्टियां भी नियमति वेतन पर अपने कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में नारे लगाने व प्रदर्शन करने के लिए रखने लगी है। ऐसे वेतनभोगी कर्मचारियों को नारे की गुणवत्ता व राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रदर्शन में यदि पुलिस की लाठी अथवा किसी भी प्रकार से मौत हो गयी तो उनके परिवार को अच्छी खासी मोटी रकम दिलवाने के लिए कोशिश की जायेगी और इस मुआवजे की राशि में भी उनका नेता व ठेकेदार अपना कमीशन झाड़ लेता है।

लगभग एक दशक के राजनीतिक परिदृश्य में देश के राजेनता विषम परिस्थितियों में राजनेता जुबानी संयम खो रहे है। एक दो दशक पूर्व तक चुनावों में छोटे से बड़े राजनेता भाषण देते थे पर कोई भी किसी विपक्षी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता था। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन से मिलने जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी तो उनकी तलाशी ली गई थी। इसे देश के सभी आम जनता में क्रोध का ज्वार आ गया था सभी आम आदमी इस बात पर सहमत थे कि यह भारत के हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करने की नापाक कोशिश की गई है। यह पूरे देश का अपमान है तथा हम सब का अपमान है। राजीव गांधी के जमाने में वी पी सिंह के समर्थक नारे लगाते थे कि गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है। परन्तु किसी भी छोटे बड़े नेता व स्वंय वीपी सिंह ने चुनावी मंच से यह नारे नहीं लगवाये थे। सभी लोग इस बात से सहमत थे कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे भाब्दों का प्रयोग करना गलत है। प्रध ाानमंत्री का अपमान देश का अपमान है। मोरार जी के स्वमूत्र सेवन का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेसियों ने सर्वाजनिक

मुत्रालयों पर मोरार जी बार लिख दिया था परन्तु मंच से किसी भी नेता ने तथा ऐसा कभी कांग्रेसी नेता ने भी नहीं कहा। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन पर भी निजी हमले किये गये। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष के नेताओं ने सिर्फ यही कहा गया कि वह मौन मोहन सिंह है सोनिया की कठपुतली है। परन्तु उनके विरुद्ध अपशब्द नहीं बोले गये।

परन्तु अब कांग्रेस सोनिया कांग्रेस बन चुकी है तो एक चुने हुए वैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा। यह कांग्रेस की निम्न स्तर की ओर जाती भाषा बन रही थी। अब राहुल गांधी चौकीदार चोर है न केवल स्वंय कह रहे है बल्कि रैलियों में जनता से नारे भी लगवा रहे है। उनके प्रवक्ता टी वी पर बहस में भी यही नारे लगा रहे है। कांग्रेस में यह बैचेनी आम आदमी महसूस कर रहा है। आम आदमी सोच रहा है कि चौकीदार चौकन्ना है, चोरी नहीं करने दे रहा है जिन्होंने पहले चोरी की थी उन्हें भी अदालत के कठघरे में खड़ा कर रहा है वही लोग चिल्ला रहे है क्योंकि वे सोचते है कि इस शोर से घबरा कर चौकीदार चौकीदारी करना छोड़ देगा और उनकी लूट फिर से शुरु हो जायेगी। मोदी के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए सभी विपक्षी दल किसी भी सीमा तक एक होकर पाकिस्तान तक से सहायता मांग रहे है जिसको आम आदमी स्पष्ट रुप से देख व सुन रहा है। आम आदमी देश की स्वतंत्रता प्राप्त करते समय भी जागरुक था और आज भी जागरुक है। उसकी इसी जागरुकता के कारण लोकतंत्र भारत में सुरक्षित है। आम आदमी यह भी देख रहा है कि विपक्ष व विशेष रुप से राहुल गांधी के द्वारा चुनावी मंचों पर मोदी पर लगने वाले आरोप मोदी पर चिपक नहीं रहे है तो इससे राहुल गांधी की नकारात्मकता ही दृष्टिगोचर होती है जिसका दुष्परिणाम सम्पूर्ण कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 में तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान आठ लोगों की मृत्यु हुई जिस पर दुख प्रकट करने के लिए अपने लावलश्कर के साथ राहुल गांधी 6 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर जाना चाहते थे तथा उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल भी थे तथा उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मृतक किसानों के परिवारों को 50 – 50 लाख रुपये (एक–एक करोड़ रुपये) के मुआवजे की घोषणा कर दी। इस सब राजनतिक स्टंट के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी यह सब भी आम नागरिक देख रहा है। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ. प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

(पृष्ठ 14 से आगे ....)

वायु प्रदूषणः अगर इच्छाएं द्रुतगामी होती...

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक भावी कमोडिटी उत्पादन में बाधा डालेगा, प्राकृतिक गैस से लेकर पर्यावरण के अनुकूल सामग्री तक हर चीज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि बड़ी मात्रा में पानी और बिजली की खपत करने वाली कंपनियों के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताएं नई नहीं हैं और अक्सर स्थानीय प्रदूषण में योगदान करती हैं, तांबे, एल्यूमीनियम और लिथियम जैसी सामग्रियों की मांग – रिचार्जेबल बैटरी का एक प्रमुख घटक जो इलेक्ट्रिक कारों को शक्ति प्रदान करता है – बढ़ने की उम्मीद है यहां तक कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं (उनके खनन से संबंधित) उनकी आपूर्ति को सीमित करती हैं। उदाहरण के लिए, जबकि कुछ अमेरिकी राज्य महत्वपूर्ण सामग्रियों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, स्थानीय विरोध और लंबी अनुमति प्रक्रिया है। दुनिया के बहुत कम हिस्से ऐसे हैं जो पर्यावरणीय मुद्दों से मुक्त हैं। चारों ओर पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण आपूर्ति में व्यवधान और परियोजना में देरी होती है।

इतना ही नहीं, हरित अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन कई व्यवधानों का कारण बनेगा। उदाहरण के लिए, कोयले से चलने वाले संयंत्र, आईसीई ऑटोमोटिव, और अन्य जैसे कई उद्योग एक मंद भविष्य का सामना करेंगे। यह रोजगार बाजार को बाधित करेगा क्योंकि हरित प्रौद्योगिकियां आमतौर पर कम श्रम गहन होती हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों में चलने वाले पुर्जे कम होते हैं और इसलिए उन्हें कम श्रम की आवश्यकता होगी। चूंकि हर सामान अधिक महंगे हैं, कीमत स्थिरता खतरे में होगी। परिणामी मुद्रास्फीति लोकतंत्र में अधिकांश सरकारों के लिए अनुकूल होने की संभावना नहीं है। अंत में, अगर पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में गिरावट आती है, तो विशेष रूप से भारत में कर राजस्व का बहुत नुकसान होगा। किसी को यकीन नहीं है कि सरकार इन लागतों को वहन करने की स्थिति में है। नतीजतन प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की दिशा में चल रहे आंदोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

संक्षेप में हम कह सकते है कि पर्यावरण की सफाई का लक्ष्य वास्तव में सरकार की प्रशंसनीय पहल है, पर इसे लेकर कोई शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से इस मामले में गति बढ़ानी होगी, नही तो परिणाम 'जंगली हंस का पीछा' करने जैसा हो सकता है। ❑❑

तेल के ऊँचे दामः लाभ भी, संकट भी

वर्ष 2015 में विश्व बाजार में तेल के दाम उछल रहे थे और 111 अमरीकी डालर प्रति बैरल के स्तर पर थे। इसके बाद 2020 में कोविड संकट के दौरान इनमें भारी गिरावट आई और दाम केवल 23 डालर प्रति बैरल रह गये। वर्तमान में पुनः इसमें कुछ वृद्धि हुई है और ये मूल्य आज 76 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गये हैं। इसी अवधि में देश के घरेलू बाजार में पेट्रोल के दाम की चाल बिलकुल अलग रही है। 2015 में घरेलू बाजार में पेट्रोल के दाम 70 रूपये प्रति लीटर थे। जब 2020 में विश्व बाजार में तेल के दाम घटकर 23 डालर प्रति बैरल हो गये थे, उस समय हमारे बाजार में तेल के दाम घटे नहीं बल्कि 70 रूपये प्रति लीटर के लगभग ही बने रहे। कारण यह कि जैसे–जैसे विश्व बाजार में तेल के दाम में गिरावट आई, उसी के समानांतर हमारी केंद्र सरकार ने तेल पर वसूल की जाने वाली एक्साइज डयूटी एवं राज्य सरकारों ने तेल पर वसूल की जाने वाली सेल टैक्स में वृद्धि की। नतीजा यह हुआ कि विश्व बाजार में जितने दाम में गिरावट आई उतना ही घरेलू टैक्स में वृद्धि हुई और बाजार में पेट्रोल का दाम 70 प्रति लीटर पर ही टिका रहा। इसके बाद इस वर्ष 2021 में विश्व बाजार में तेल के दाम पुनः बढ़े हैं और जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वर्तमान में ये 76 डालर प्रति बैरल पर आ गये हैं, लेकिन इस समय घरेलू दाम स्थिर नहीं रहे। विश्व बाजार में तेल के दाम के समानांतर घरेलू बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। 2020 के 70 रूपये से बढ़कर आज ये दिल्ली में 102 रूपये प्रति लीटर हो गये हैं।

इस वर्ष में जैसे–जैसे विश्व बाजार में ईधन तेल के दाम बढ़े उस समय हमारी सरकार ने तेल पर वसूल किये जाने वाले टैक्स में कटौती नहीं की है और घरेलू बाजार में तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार मालामाल हो रही है। वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार को तेल से 72 हजार करोड़ रूपये का राजस्व मिला था जो वर्तमान वर्ष में 300 हजार करोड़ रूपये होने का अनुमान है। यानि 2015 और आज की तुलना करें तो विश्व बाजार में तेल के दाम उस समय के 111 डालर से घटकर वर्तमान में 76 डालर रह गया है लेकिन केन्द्र सरकार का राजस्व 72 हजार करोड़ से बढ़कर 300 हजार करोड़ हो गया है। बिलकुल स्पष्ट है कि

मेरे अनुमान से यदि और भी वृद्धि की जाए तो भी सही होगा लेकिन शर्त यह है कि उससे अर्जित रकम का उपयोग नये निवेश के लिए किया जाए न कि सरकार की खपत को पोषित करने में।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

सरकार ने वर्तमान में ईधन तेल पर भारी टैक्स वसूल किया है।

तेल के ऊँचे दाम का एक विशेष प्रभाव यह है कि महंगाई में वृद्धि होती है। पेट्रोल के साथ डीजल के दाम बढ़ते हैं जिससे माल की ढुलाई महंगी हो जाती है और बाजार में प्रत्येक माल महंगा हो जाता है। लेकिन केयर रेटिंग के अनुसार पेट्रोल के दाम का हमारे थोक मूल्य सूचकांक में 1.6 प्रतिशत का हिस्सा होता है और डीजल का 3.1 प्रतिशत का। यानी पेट्रोल के दाम में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो थोक मूल्य सूचकांक में केवल 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्तमान में पेट्रोल के दाम में 2015 की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है... 70 रूपए से बढ़कर यह 102 रूपए हो गए हैं। इस वृद्धि से थोक मूल्य सूचकांक में मात्र 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी ऐसा माना जा सकता है। डीजल के दाम में जो 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसका हमारे थोक मूल्य सूचकांक में प्रभाव 1.5 प्रतिशत माना जा सकता है। दोनों का सम्मिलित प्रभाव मात्र 2.5 प्रतिशत माना जा सकता है। तुलना में 2015 से 2021 के बीच में महंगाई इससे कहीं ज्यादा बढ़ी है। इससे स्पष्ट है कि महंगाई पर पेट्रोल के दाम में वृद्धि का प्रभाव कम और अन्य कारकों का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोल के दाम में वृद्धि का महंगाई पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

पेट्रोल के दाम में वृद्धि का दूसरा संभावित प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों पर पड़ सकता है। लेकिन अपने देश में अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बिजली से चलते हैं जिसका दाम बीते कुछ वर्षों में लगातार गिर रहा है। इसलिए उद्योगों पर भी पेट्रोल के बढ़े दाम का नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखता है।

पेट्रोल के दाम में वृद्धि का एक लाभ यह है कि हमारी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा होती है। हम अपनी खपत का 85 प्रतिशत पेट्रोल आयात करते हैं जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था आयातों पर निर्भर हो जाती है। किसी भी वैश्विक संकट के समय हम दबाव में आ सकते हैं। जब घरेलू बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो लोग उर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग जादा करते हैं जैसे बस से यात्रा ज्यादा करना चाहेंगे जिसमें ईधन की खपत कम होती है; अथवा बिजली की कार अथवा मेट्रो का उपयोग करेंगे। इसलिए तेल के दाम बढ़ने से देश में पेट्रोल की खपत कम होगी, हमारी आयातों पर निर्भरता कम होगी और हमारी आर्थिक सम्प्रभुता की रक्षा होगी। तेल के ऊँचे दाम का दूसरा लाभप्रद प्रभाव पर्यावरण का है। तेल के जलने से कार्बनडाईआक्साइड का भारी मात्रा में उत्सर्जन होता है फलस्वरूप धरती का तापमान बढ़ रहा है। बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं। इसलिए तेल के ऊँचे मूल्य मूल रूप से देश के लिए लाभप्रद हैं।

लेकिन संकट यह दिखता है कि तेल के ऊँचे मूल्य से वसूल किये गये राजस्व का उपयोग सरकार अपनी खपत को पोषित करने के लिए कर रही है। वर्तमान वर्ष 2021–22 में सरकार के पूंजी खर्च में 115 हजार करोड़ की वृद्धि हुई जबकि पूंजी कि बिक्री से 142 हजार करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है। यानि तेल से अर्जित अतिरिक्त आय का उपयोग पूंजो खर्चों को बढाने में नहीं किया गया है। इसी क्रम में जनकल्याण योजनाओं में भी खर्च में वृद्धि नहीं हुई है। उदहारणत के लिए मनरेगा में 34 प्रतिशत की कटौती हुई है और प्रधानमंत्री किसान योजना में 10 हजार करोड़ की कटौती हुई है। इससे स्पष्ट है कि तेल से अर्जित अतिरिक्त राजस्व का उपयोग सरकार अपने कर्मियों को वेतन देने अथवा अन्य खपत में कर रही है जो कि अनुचित है। अतः सही नीति यह है कि तेल दामों में वृद्धि की जाए। मेरे अनुमान से यदि और भी वृद्धि की जाए तो भी सही होगा लेकिन शर्त यह है कि उससे अर्जित रकम का उपयोग नये निवेश के लिए किया जाए न कि सरकार की खपत को पोषित करने में।❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

चीन की बिजली गुल, भारत पर कैसे पड़ेगा असर

चीन इन दिनों बिजली की भारी कटौती से जूझ रहा है और वहां लाखों घर और कारखाने इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। चीन में पावर ब्लैकआउट असामान्य नहीं है लेकिन इस बार कई अन्य वजहों ने चीन के बिजली आपूर्तिकर्ताओं के लिए मुसीबत को और भी बड़ा कर दिया है। बिजली की भारी कटौती का सामना कर रहे चीन के पूर्वोत्तर हिस्से के 'इंडस्ट्रियल हब' में यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। चीन विश्व के अधिकांश देशों के लिए मुख्य आपूर्तिकर्ता बना हुआ है इसलिए वहां उत्पादन बंद या कम होने से प्रभाव दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी पड़ सकता है।

बीते वर्षों के दौरान चीन ने बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष किया है जिसकी वजह से चीन के कई प्रांतों में बिजली की कटौती का संकट पैदा हुआ। साल 2021 में और भी कई ऐसे मुद्दे आए जिसने इस समस्या को और भी विकराल बना दिया।कोरोना महामारी के बाद जैसे जैसे पूरी दुनिया एक बार फिर खुलने लगी चीन के सामानों की मांग भी बढ़ने लगी और उन्हें बनाने वाले चीन के कारखानों को इसके लिए अधिक बिजली की ज़रूरत पड़ी।

चीन की सरकार ने 2060 तक देश को कार्बन मुक्त बनाने के लिए जो नियम बनाए है उसकी वजह से कोयले का उत्पादन पहले से धीमा पड़ा है। इसके बावजूद अपनी आधी से अधिक ऊर्जा ज़रूरतों के लिए चीन आज भी कोयले पर ही निर्भर है। जैसे–जैसे बिजली की मांग बढ़ी है, कोयला भी महंगा हो रहा है। चीन की सरकार अपने देश में बिजली की कीमतों को सख्ती के साथ नियंत्रित करती है, ऐसे में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट घाटे में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनमें से कई ने तो अपने उत्पादन में कटौती कर दी है।

ब्लैकआउट से चीन के कई प्रांतों और इलाक़ों में घरों और व्यवसायों पर असर पड़ा जहाँ बिजली की आपूर्ति सीमित हो गई है। दक्षिण चीन के ग्वांग्डोंग और पूर्वोत्तर चीन के

भारतीय उधमियों के लिए यह मौका एक अवसर हो सकता है। भारत सरकार के साथ मिलकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को चीन से आयात किये जाने वाले उत्पादों को विशेषज्ञों की मदद से स्थानांतरित या भारत में ही उत्पादन इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है।

– दुलीचंद कालीरमन

हेइलोंगजियांग, जिलिन और लिआओनिंग में बिजली आपूर्ति में समस्या आ रही है। देश के अन्य हिस्सों में भी पावर-कट होने के समाचार मिल रहे हैं। उद्योगों वाले इलाक़ों में कई कंपनियों से कहा जा रहा है कि वे 'पीक टाइम' में बिजली के इस्तेमाल में कटौती करें या फिर अपने काम के दिन कम कर दें। इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट और उर्वरक से जुड़े उद्योगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है जहाँ बिजली की काफ़ी ज़रूरत होती है।

बिजली गुल होने से चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरित असर पड़ा है। चीन के आधिकारिक आँकड़े दिखाते हैं कि सितंबर 2021 में चीन के कारखानों में फ़रवरी 2020 के बाद से काम सबसे कम हो गया है जब कोरोना संक्रमण के बाद हुए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को ठप्प कर दिया था।

बिजली आपूर्ति को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बाद अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंकों ने अपने अनुमानों में चीन के आर्थिक विकास की दर को घटा दिया है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक़ पावरकट की वजह से चीन की औद्योगिक गतिविधि 44 प्रतिशत तक कम हो गई है। बैंक का अनुमान है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वर्ष 7.8 प्रतिशत की दर से विकास करेगी, जबकि पहले उसने इसके 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

लेकिन कोयले की आपूर्ति बढ़ाना इतना सहज नहीं है। रूस जहाँ पहले से ही यूरोप के अपने ग्राहकों पर ध्यान दे रहा है, वहीं इंडोनेशिया में भारी बारिश से कोयले की सप्लाई पर असर पड़ा है और पास का देश मंगोलिया सड़क के रास्ते ढुलाई को लेकर पहले से ही जूझ रहा है।

चीन में बिजली संकट गहराने से भारत में कई वस्तुओं के कच्चे माल की

चीन में समस्या उत्पन्न होने से दुनिया के सभी हिस्सों में सप्लाई चेन प्रभावित होगी जिससे कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है।

आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका गहराने लगी है। इनमें मुख्य रूप से विभिन्न रसायन व दवा के कच्चे माल, स्टील, फर्नेस आयल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रानिक्स व आटो पार्ट्स शामिल हैं। फिलहाल चीन में उत्पादन प्रभावित होने से भारत में केमिकल्स के दाम में बढ़ोतरी होने लगी है। लेकिन निकट भविष्य में अन्य कच्चे माल की कीमतों में भी बढ़ोतरी का अंदेशा प्रबल होने लगा है।

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशंस (फियो) के अनुसार बिजली संकट की वजह से चीन के 20 प्रांतों में मैन्यूफैक्चोरग प्रभावित है और देश की लगभग 45 फीसद मैन्यूफैक्चरिंग बंद है। अगले 10-15 दिनों के बाद कई कच्चे माल की आपूर्ति पर असर दिख सकता है। केमिकल्स उद्यमियों ने बताया कि चीन के संकट के कारण पिछले 15 दिनों में भारत में केमिकल्स के दाम पांच से 40 फीसद तक बढ़ चुके हैं। हालांकि दवा निर्माताओं का कहना है कि उनके पास अमूमन 45 दिनों के कच्चे माल का स्टाक रहता है। अगर बिजली संकट उसके बाद भी जारी रहता है तो निश्चित रूप से दवा के कच्चे माल की कमी हो सकती है। दवा के कच्चे माल के लिए भारत अब भी चीन पर निर्भर है और 70 प्रतिशत कच्चा माल चीन से ही आता है।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जनवरी-अगस्त में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले चीन से आटो पार्ट्स के आयात में 70.56 फीसद, इलेक्ट्रिकल्स व संबंधित पार्ट्स में 64.29, प्लास्टिक में 108.99, लौह अयस्क व स्टील में 37.84, फार्मा उत्पाद में 38 और केमिकल्स के आयात में 41 फीसद का वृद्धि हुई है।

चीन में कोयला संकट से उत्पादन के साथ वहां बंदरगाहों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई है। इससे भारत में कंटेनर समस्या और गहरा सकती है जिससे लागत बढ़ेगी। निर्यात-आयात से जुड़े व्यापारियों के मुताबिक चीन कमोबेश दुनियाभर को कच्चे माल की सप्लाई करता है। ऐसे में चीन में समस्या उत्पन्न होने से दुनिया के सभी हिस्सों में सप्लाई चेन प्रभावित होगी जिससे कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है।

भारतीय उधमियों के लिए यह मौका एक अवसर हो सकता है। भारत सरकार के साथ मिलकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को चीन से आयात किये जाने वाले उत्पादों को विशेषज्ञों की मदद से स्थानांतरित या भारत में ही उत्पादन इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है। इसकी राह में आने वाली सभी बाधाओं को त्वरित गति से दूर करने की आवश्यकता है, ताकि रणनीतिक तौर पर भी भारत को आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल कर सके। ❑❑

"युवा, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत"

किसी भी देश का विकास वहाँ के लोगों के विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जीवन के हर पहलू में विज्ञान–तकनीक और शोध कार्य अहम भूमिका निभाएँ। विकास के पथ पर कोई देश आज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी आने वाली पीढ़ी के लिये सूचना और ज्ञान आधारित वातावरण बने और उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध तथा अनुसंधान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। इस पूरी प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी के स्तर पर खड़ा है तो सरकार, समाज और व्यवस्था की यह जिम्मेदारी है उसी युवा को बेहतर तकनीक और शोध नवाचार के सभी अवसर मुहैया कराए जाएं ताकि वह अपने योग्यता, लगन और ज्ञान से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे सके। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ–साथ भारत की युवा आबादी और उसकी कार्य क्षमता पर आधारित हैं.

अगर हम कुछ तथ्यों को देखें तो, इंडियन साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष रैंकिंग वाले देशों में शामिल है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति भी भारत में ही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा संचालित शोध प्रयोगशालाओं के ज़रिये नानाविध शोधकार्य किये जाते हैं। मौसम पूर्वानुमान एवं निगरानी के लिये प्रत्युष नामक शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर बनाकर भारत इस क्षेत्र में जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद चौथा प्रमुख देश बन गया है। नैनो तकनीक पर शोध के मामले में भारत दुनियाभर में तीसरे स्थान पर है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index) में हम 57वें स्थान पर हैं। भारत ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की स्थिति में पहुँच रहा है और विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक स्वदेश लौट रहे हैं। व्यावहारिक अनुसंधान गंतव्य के रूप में भारत उभर रहा है

वैश्विक नवाचार सूचकांक में हम 57वें स्थान पर हैं। भारत ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की स्थिति में पहुँच रहा है और विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक स्वदेश लौट रहे हैं।

– अभिषेक प्रताप सिंह

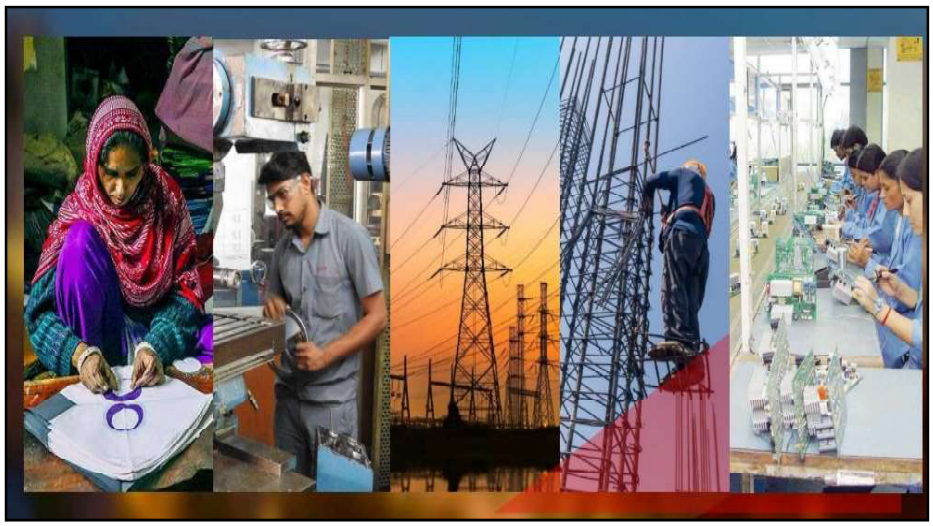

तथा पिछले कुछ वर्षों में हमने अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाया है। वैश्विक अनुसंधान एवं विकास खर्च में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। देश में मल्टी–नेशनल कॉर्पोरशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्रों की संख्या 2018 आँकड़ों के अनुसार 1150 तक पहुँच गई है। ये सभी बदलाव, भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों की रफ्तार कई क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रही है।

आज हमारे देश का युवा वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, विनिर्माण, जैव–ऊर्जा, जल–तकनीक, और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।

वैश्विक स्तर पर भारतीय और आसियान शोधकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों और नवोन्मेषकों के बीच नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से आसियान–भारत इनोटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और स्वच्छ विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत–UK साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी डायलॉग के द्वारा दोनो देश सहयोग कर रहे हैं।

युवा विद्यार्थियों के लिये ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। डीडी साइंस और इंडिया साइंस नाम की दो नई पहलों की भी शुरुआत हुई है।

इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन और कार्य प्रौद्योगिकी विकास तथा राष्ट्र निर्माण के साथ गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो इशारा करते हैं कि भारत आज विश्व में वैज्ञानिक प्रतिस्पर्द्धा के क्षेत्र में कहाँ ठहरता है? आखिर क्यों भारत शोध कार्यों के मामले में चीन, जापान जैसे देशों से पीछे है? ऐसी कौन–सी चुनौतियाँ हैं जो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पहिये को रोक रही हैं? इस दिशा में क्या कुछ समाधान किये जा सकते हैं? आवश्यक है आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना इन सभी समस्याओं के समाधान के आलोक में सुनिश्चित हो। तब ही सही मायने मे हम अपने राष्ट्र संकल्प को प्राप्त कर सकेंगे।

अभी पिछले दिनों जब हमने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ऐसे समय में इस देश की युवा आबादी के लिए आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य एक सबसे बड़ी प्रेरणा है. इन सब बातों के मद्देनज़र एक ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक प्रसार और नवाचार को बढ़ावा देने और सभी सामाजिक स्तरों से युवाओं के बीच विज्ञान के अनुप्रयोगों के लिये कौशल को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाए जो कि एक उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण मे यही सही कदम होगा। ❑❑

(लेखक डा अभिषेक प्रताप सिंह देशबंधु कालेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापक हैं।)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

'भारतीय संस्कृति के मूल में है महिला सशक्तिकरण'

गत दिनों देश की शीर्ष अदालत ने समानता के अधिकार के तहत लड़कियों को एनडीए परीक्षा में शामिल होने का अंतरिम आदेश पारित किया। अभी तक नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा एवं सुरक्षा करने का अधिकार केवल देश के पुरूष वर्ग को प्राप्त था परन्तु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परचम लहराने वाली लड़कियां भी अब राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। कोर्ट का यह आदेश निश्चित ही,महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। स्वतंत्र भारत में यह अधिकार भले ही बालिकाओं को पहली बार मिला हो परन्तु वैदिक काल में, बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा दीक्षा के अतिरिक्त शस्त्र चलाने एवं घुड़सवारी करने का समान रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था। राष्ट्र की रक्षा एवं सुरक्षा हेतु दुश्मनों से लोहा लेने व रणभूमि में अपने प्राण न्योछावर करने वाली अनेकों वीरांगनाओं से इस देश का इतिहास भरा पड़ा है।

वैदिक हिन्दू संस्कृति – सभ्यता, संस्कार एवं परम्पराओं के वाहक लाखों वर्ष पुराने वेदों में नारी को पुरुषों से उच्च स्थान दिया गया है। वेदों के अनुसार स्त्री यज्ञीय है अर्थात यज्ञ के समान पूजनीय एवं पवित्र है, साथ ही ज्ञान एवं सुख समृद्धि देने वाली देवी, विदुषी, इंद्राणी जैसे अनेकों नामों से उसे सम्बोधित किया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत और महत्वपूर्ण होने के साथ उसे परिवार और समाज दोनों स्थानों पर उचित सम्मान दिया जाता था। शिक्षा का समान अधिकार होने के कारण उसे समितियों और सभाओं में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। घुड़सवारी एवं शस्त्र चलाने में पुरुषों के समान दक्षता हासिल होने के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के अतिरिक्त अनुष्ठान क्रियाएं सम्पन्न कराने वाले पुरोहितों एवं ऋषियों तक का दर्जा प्राप्त था। महिलाएं धर्म शास्त्रार्थ में पुरुषों के समान बढ़ चढ़कर भाग लेती थीं इसका उदाहरण विदुषी गार्गी हैं जिन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। नारियों को परिपक्व उम्र में स्वयंवर के द्वारा अपना वर चुनने की पूर्ण आजादी थी। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान या कहें उससे ज्यादा अधिकार, सम्मान एवं स्वतंत्रता प्राप्त थी। वेदों में अनेकों ऐसे श्लोक वर्णित हैं जो नारी के अध्ययन, अध्यापन, राजनीति, श्रवण एवं वाचन में समान अधिकार के पक्षधर होने के साथ समस्त सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का

आज भारत सबसे तेज गति से आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हो गया है, इसमें कहीं न कहीं महिलाओं की भी अहम भागीदारी है निश्चित ही, नारी की स्थिति में निरंतर सुधार, राष्ट्र की प्रगति का मापदंड है।

डॉ. अनुपमा अग्रवाल

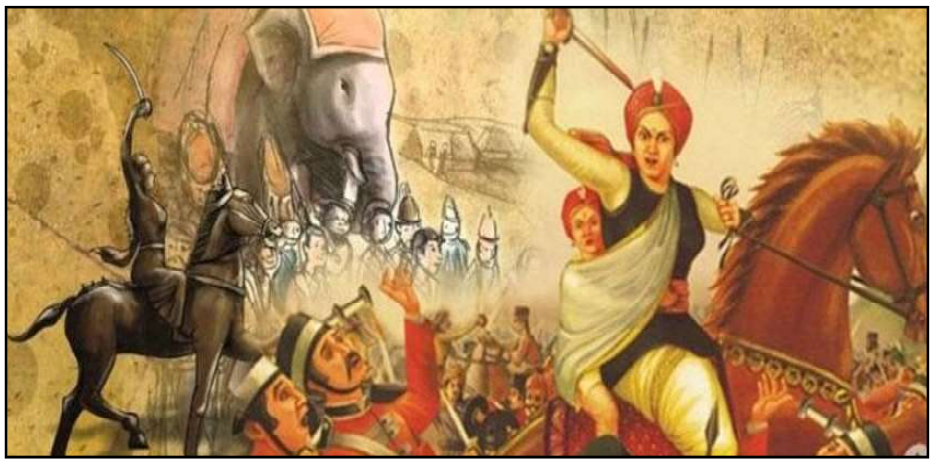

वर्णन करते हैं। मैत्रेयी, अपाला, गार्गी, विश्वआरा, रत्नावली, लोपामुद्रा आदि कुछ ऐसी विदुषी नारियां हैं, जिनकी चर्चा वेदों में की गई है।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और सशक्त थी। महिलाएं कृषि एवं बाजार हाट आदि के कार्यों में पुरूषों का हाथ बटाया करती थीं। गणिकाएं भी नृत्य, संगीत, श्रृंगार, गायन आदि में कुशल होती थीं। नृत्य व संगीत उनकी आजीविका के साधन थे, वे केवल मनोरंजन की सामग्री मात्र नहीं थीं वरन संगीत की उपासना के साथ राज्यों में युद्ध के भेदिये जैसे दुष्कर कार्यों के लिए भी समर्पित रहती थीं। वे आय का एक भाग राज्य को कर के रूप में भी देती थीं। नारी द्वारा सूत कातना, वस्त्र बुनने आदि का उल्लेख भी इतिहास में मिलता है। 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के मध्य विदेशी आक्रमणकारियों एवं मुगलों के शासन काल में महिलाओं की जिदंगी बद्तर हो गई। उन पर अत्याचार होने लगे तथा अधिकारों का हनन होने के कारण उन्हें गुलामों की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। इस काल में रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, चिन्नम्मा, बेगम हजरत महल, पद्मावती आदि कुछ ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी, साहस एवं हिम्मत के बल पर स्वयं के स्वाभिमान को बचाये रखते हुए राष्ट्र की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 19वीं सदी में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ। शिक्षा की अनिवार्यता ने महिलाओं को न केवल घर की चारदीवारी से बाहर निकाला बल्कि समान अधिकारों के चलते महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा किया। शिक्षा के कारण महिलाएं रूढ़िवाद की कोठरी से बाहर निकल स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने लगीं और कभी पुरूष को बैसाखी बनाकर चलने वाली महिलाएं स्वयं अपने बलबूते आसमान छूने लगीं।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सुदृण और सशक्त थी। महिलाएं कृषि एवं बाजार हाट आदि के कार्यों में पुरूषों का हाथ बटाया करती थीं।

वर्तमान परिदृश्य में महिलाएं न केवल घर परिवार को भलीभांति संभाल रही हैं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर स्वयं को नए मुकाम पर स्थापित करने में भी सफल हो रही हैं। महिलाओं को उनकी प्रतिभा निखारने एवं आगे बढ़ाने में तत्कालीन मोदी सरकार की भी अहम भूमिका रही है। सरकार द्वारा वंचित बस्तियों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम एवं स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा के अतिरिक्त महिलाओं के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास योजना के तहत युवक युवतियों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण के उपरांत अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की सरकार की योजना चालू है, ताकि घरों अथवा फैक्ट्री में कार्य करने वाली महिलाएं आर्थिक शोषण से बच सकें और छोटे पैमाने पर घर से अपना व्यापार चालू कर सकें। महिला सशक्तिकरण को लेकर वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास कोरोना काल में रंग लाते दिखे। लॉकडाउन के समय जब आमजन घर की चारदीवारी के भीतर रहने को मजबूर था और काफी लोगों की नौकरी पर संकट आने के कारण रोजीरोटी छिन गई थी। उस समय महिलाओं ने अचार, पापड़, मठरी, मास्क, राखी निर्माण व हस्तशिल्प सामग्री आदि का घर से निर्माण कर उसका ऑनलाइन व्यापार चालू कर न केवल अपने परिवार का पेट पाला बल्कि स्वयं आत्मनिर्भर बन अब अन्य लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं।

आज की नारी ने यह साबित कर दिया है कि वह कोमल है पर कमजोर नहीं। उसमें पन्नाधाय का त्याग है तो रानी लक्ष्मीबाई सा साहस भी, अवनि चतुर्वेदी सी बहादुरी है तो अरुणिमा सिंह जैसा साहस भी, कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स जैसी अंतरिक्ष विजय करने की क्षमता है तो बछेंद्री पाल जैसी पर्वत फतह करने की हिम्मत भी, पीटी उषा जैसा जीत का जज्बा है तो लक्ष्मी सॉ जैसी जीवटता भी, दीपा कर्माकर जैसा जुनून है तो सुरसम्राज्ञी लता मंगेशकर जैसी मधुरता भी, स्व. सुषमा स्वराज जैसी राजनीतिज्ञ है तो इंदिरा नूई जैसी सफल व्यवसायी भी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्र में न् जाने ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं जो महिला सशक्तिकरण के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो ये दर्शाते हैं कि आज की नारी अबला नहीं सबला है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सक्षम और सबल बन परिवार के साथ राष्ट्र की प्रगति, रक्षा और निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने की हिम्मत रखती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी व स्वामी विवेकानंद जी का कथन था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी पक्षी का एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं है।

आज भारत सबसे तेज गति से आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हो गया है, इसमें कहीं न कहीं महिलाओं की भी अहम भागीदारी है निश्चित ही, नारी की स्थिति में निरंतर सुधार, राष्ट्र की प्रगति का मापदंड है।❑❑

अनुपमा अग्रवाल (स्तंभ लेखिका), अलीगढ़

शिक्षा और पर्यावरण का तन्त्र डुबा रहा है अर्थव्यवस्था को

स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलोपमेंट द्वारा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 2016 में 41 से फिसलकर 2020 में 43 रह गयी है। इसी के समानांतर वर्ल्ड इकनामिक फोरम द्वारा बनाये गये प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2018 में भारत की रैंक 58 थी जो कि 2019 में फिसलकर 68 रह गयी है। इस प्रकार विश्व के 2 प्रमुख प्रतिस्पर्धा मानकों में हम फिसल रहे हैं। यदि हमारी यही चाल रही तो देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था को बनाने का सपना निश्चित रूप से अधूरा रह जाएगा।

हमारे फिसलने के दो प्रमुख कारण दिखते हैं। पहला कारण शिक्षा का है। इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलोपमेंट के अनुसार भारत का शिक्षा तंत्र 64 देशों में 59 वें रैंक पर था। हम लगभग सबसे नीचे थे। पर्यावरण की रैंक में हम 64 देशों में अंतिम पायदान यानी 64 वें रैंक पर थे। विश्वगुरु का सपना देखने वाले देश के लिए यह शोभनीय नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारा खराब प्रदर्शन चिंता का विषय है, क्योंकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुसार वर्ष 2019–20 में हमने अपनी आय यानी जीडीपी का 3.3 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया था। यद्यपि वैश्विक स्तर पर शिक्षा पर 6 प्रतिशत खर्च को उचित माना जाता है फिर भी 3.3 प्रतिशत उतना कमजोर नहीं है। यह रकम 2019–20 में 651 हजार करोड़ रूपये की विशाल राशि बन जाती है। ऐसा समझें कि 6 माह में हमारी जनता जितना जीएसटी अदा करती है और केन्द्र एवं राज्य सरकारों को जितना राजस्व मिलता है उससे अधिक खर्च इन सरकारों द्वारा शिक्षा पर किया जा रहा है। फिर भी शिक्षा में हमारी रैंक 64 देशों में 59 है, जो कि शर्मनाक है. जाहिर है कि शिक्षा पर किये जा रहे खर्च में कहीं न कहीं विसंगति है।

651 हजार करोड़ रूपये की राशि सरकार द्वारा हर वर्ष शिक्षा पर खर्च की जा रही है। यह रकम केवल सरकारी विद्यालयों में पढने वाले छात्रों पर की जा रही है। दिल्ली में प्रति छात्र 78,000 रूपए खर्च किये जा रहे हैं। वर्तमान में हमारी विद्यालय जाने वाली

शिक्षा के क्षेत्र में हमारा खराब प्रदर्शन चिंता का विषय है, क्योंकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुसार वर्ष 2019–20 में हमने अपनी आय यानी जीडीपी का 3.3 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया था।

– स्वदेशी संवाद

जनसंख्या लगभग 46 करोड़ है। यदि इस रकम को देश के सभी छात्रो में बाँट दिया जाये तो प्रत्येक छात्र को 14,000 रूपए दिए जा सकते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण इंगलिश मीडियम विद्यालयों की फीस लगभग 12 हजार रूपये प्रति वर्ष होती है। यानी जितनी फीस में प्राइवेट विद्यालयों द्वारा इंगलिश मीडियम की शिक्षा हमारे छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है उससे 5 गुणा रकम सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढने वाले छात्रों पर की जा रही है। एक ओर प्राइवेट इंगलिश मीडियम स्कूल 12 हजार रूपये में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं दूसरी तरफ 78 हजार रूपये सरकार द्वारा खर्च किये जाते हैं। इसके बावजूद हमारी रैंक नीचे रहती है। इस विसंगति का मूल कारण यह दिखता है कि सरकारी अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने में कोई रूचि नहीं होती है। यदि उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है और यदि उनके रिजल्ट खराब आते हैं तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है। इसलिए उनके लिए विद्यालय की बायोमेट्रिक व्यवस्था में अपनी हाजिरी लगाना मात्र ही उद्देश्य रह जाता है।

विशेष यह कि सरकार ने फीस माफ़ करके, मुफ्त पुस्तक, मुफ्त यूनिफार्म और मुफ्त मध्यान्ह भोजन वितरित करके छात्रों को सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने के लिए सम्मोहित कर लिया है। इस सम्मोहन के चलते वे तुलना में कम खर्च में शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों की तुलना महंगे लेकिन मुफ्त सरकारी विद्यालय में दाखिला लेना पसंद करते हैं। इसलिए यदि हमें अपनी प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाना है तो अपनी शिक्षा व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। सुझाव है कि सरकार द्वारा खर्च की जा रही रकम को छात्रों को सीधे वाउचर के माध्यम से दिया जाए और छात्रों को स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपने मन पसंद के गुणवत्ता युक्त विद्यालय में उन वाउचरों के माध्यम से अपनी फीस अदा कर सकें। यदि ऐसा किया जाएगा तो महंगे सरकारी विद्यालय में दाखिला लेने का प्रलोभन समाप्त हो जाएगा और उस रकम को कुशल प्राइवेट विद्यालयों कि शिक्षा में सुधार के लिए किया जा सकेगा. हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगा।

दूसरी समस्या पर्यावरण की है जिसमें हमें 64/64 पायदान पर सबसे नीचे है। समस्या यह है कि सरकार समझ रही है पर्यावरण के अवरोध से हमारी आर्थिक गतिविधियाँ रुक रही हैं। पर्यावरण के अवरोध को समाप्त कर अर्थव्यवस्था तो त्वरित बढ़ाना होगा। जैसे सरकार ने हाल में थर्मल बिजली संयंत्रों द्वारा प्रदूषण के मानकों को ढीला कर दिया है और पर्यावरण स्वीकृति के नियमों में ढील दी है।

दूसरी समस्या पर्यावरण की है जिसमें हमें 64/64 पायदान पर सबसे नीचे है। समस्या यह है कि सरकार समझ रही है पर्यावरण के अवरोध से हमारी आर्थिक गतिविधियाँ रुक रही हैं। पर्यावरण के अवरोध को समाप्त कर अर्थव्यवस्था तो त्वरित बढ़ाना होगा. जैसे सरकार ने हाल में थर्मल बिजली संयंत्रों द्वारा प्रदूषण के मानकों को ढीला कर दिया है और पर्यावरण स्वीकृति के नियमों में ढील दी है। सरकार का मानना है कि पर्यावरण कानून को नर्मी से लागू करने से उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाना आसान हो जाएगा और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। लेकिन प्रभाव इसका ठीक विपरीत हो रहा है। जैसा ऊपर बताया गया है कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हमारे फिसलने का एक प्रमुख कारण पर्यावरण है। प्रश्न है कि उसी पर्यावरण को और कमजोर करने से हमारी प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार कैसे संभव है? अतः सरकार को समझना होगा कि पर्यावरण रक्षा करने से ही हमारी प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ेगी। कारण यह कि जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है तो जनस्वास्थ सुधरता है और नागरिकों की कार्य क्षमता बढती है। दूसरा यह कि जब हमारा पर्यावरण साफ़ रहता है तो निवेशकों को निर्भय होकर भारत में आकर निवेश करने में संकोच नहीं होता है। वे प्रदूषित स्थानों पर उद्योग लगाने में कतराते हैं। तीसरा यह कि जब पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम साफ़ तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे यदि सरकार नियम बनाती है कि उद्योगों को उर्जा की खपत कम करनी होगी, तो उद्योगों द्वारा अच्छी गुणवत्ता की बिजली के बल्ब, पंखे, एयर कन्डीशनिंग, मोटरें इत्यादि उपयोग में लाई जाती हैं जो कि अंततः उनकी उत्पादन लागत को कम करती हैं. जिस प्रकार बच्चे को पढ़ाई करने के लिए दबाव डालना पड़ता है लेकिन पढ़ाई कर लेने के बाद उसका भविष्य उज्वल हो जाता है उसी प्रकार यदि सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्योगों पर दबाव डालती है तो अंततः उद्योग कुशल हो जाते हैं।

हमें चेत जाना चाहिए कि शिक्षा में 59/64 और पर्यावरण में 64/64 की हमारी रैंक शोभनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी प्रतिस्पर्धा रैंक गिरती जा रही है। हमें शिक्षा में वाउचर सिस्टम लागू करना चाहिए और पर्यावरण की सख्ती से रक्षा करनी चाहिये. तब हमारी अर्थव्यवस्था भी चल निकलेगी। ❑❑

(भरत झुनझुनवाला की वाल से)

अर्थ चिंतन 2021

स्वदेशी जागरण मंच की प्रेरणा से आयोजित तीन दिवसीय चर्चा "अर्थ चिंतन 2021" 25 सितम्बर को सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री सी.आर. मुकुंदा ने कहा कि अधिकांश बातें हमारे ग्रंथों में बताई हुई हैं। हमें समाज की संकल्प शक्ति बनानी होगी। संकल्प और कृतित्व से ही भविष्य बनता है। हमें समृद्धि का दृष्टिकोण बदलना होगा और इसके लिए समाज में "समृद्धि की पूजा" का भाव जागृत करना होगा। दारिद्रय किसी भी समाज को लम्बे समय तक जीवित नहीं रख सकता। समय की बर्बादी और असमर्थता से दरिद्रता आती है। जनसंख्या समस्या नहीं है, यदि जितने पेट हैं तो उससे दुगने हाथ भी हैं। हमें समृद्धि को मंत्र बनाना है, किंतु यह समृद्धि धर्म से नियंत्रित हो, यह भी सुनिश्चित करना होगा।

समृद्धि निर्माण, कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, हुनर आदि विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा होता है। यह कार्य हम अपनी वर्क फ़ोर्स की शक्ति से करें। इसके लिए छोटे समुदायों को साथ लें। समृद्धि हस्तांतरण को समृद्धि निर्माण मानने की भूल हमें नहीं करनी है। दुनिया में शेयर बाज़ार उतार चढ़ाव, टेक्स बचाव, दलाली, सनसनी से सट्टेबाज़ी आदि जैसे समृद्धि हस्तांतरण को समृद्धि निर्माण मान लिया जा रहा है। टेक्नोलोज़ी को रोकना सम्भव नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ दिमाग़ वाली सर्वाधिक युवा शक्ति भारत में है, अतः इससे लाभ उठाने का कौशल विकसित करना होगा।

मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. धनपतराम अग्रवाल ने 25 सितम्बर के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि "एकात्म मानव दर्शन" के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म आज के दिन ही हुआ था। उनका मानना था कि पूँजीवाद और साम्यवाद की व्यवस्था सरकार या निजी क्षेत्र में केंद्रीयकरण आधारित होने के कारण "कहीं धन का अभाव या कहीं धन का प्रभाव" वाली स्थिति का निर्माण करती हैं। यह स्थिति चल नहीं सकती।

अतः उसके विकल्प के रूप में उन्होंने समाज को आगे रखते हुए एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि "समाज के लिए सरकार है, न कि सरकार के लिए समाज"। इसी दर्शन को व्यावहारिक रूप में ठेंगड़ी जी नें अपनी पुस्तक तीसरा विकल्प में लिखा है। उन्होंने विस्तार से आँकड़ों के साथ विश्वास व्यक्त किया कि भारत में अगले 15 वर्षों में 27 ट्रिल्यन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की क्षमताएँ हैं।

मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने स्वदेशी जागरण मंच की तीस वर्षों की यात्रा के अनेक पड़ावों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि चीनी वस्तुओं के बहिष्कार पर मंच के जन जागरण अभियान का ही परिणाम है कि चीन से व्यापार घाटा जो कि वर्ष 2016 में 64 अरब डॉलर होता था, आज वह घटकर 44 अरब डॉलर रह गया है। उन्होंने युवाओं को मंच का स्वदेशी साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जो कि मंच की विभिन्न 3 साइट्स पर उपलब्ध है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस चर्चा को गाँवों तक ले जाकर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न को साकार करना है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना यह स्वतंत्रता अधूरी है।

सिद्धगिरी पीठ, कनेरी मठ के पूज्य स्वामी कोडसिद्देश्वर जी ने देश भर में फैले छोटे–छोटे समुदायों के सशक्तिकरण करके इस अभियान को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार के अभाव में ख़ाली होते गाँवों पर चिंता व्यक्त की। शासन द्वारा सबको मुफ़्त वितरण की सुविधा देश को आलस्य में धकेल देती है, अतः जनता को रोज़गार देकर स्वावलंबी बनाना ही एकमात्र रास्ता है। अर्थव्यवस्था के केंद्रीयकरण नें गाँवों का सर्वनाश कर दिया है। गाँव को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने कनेरी मठ के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि मात्र 3 वर्षों में कोल्हापुर ज़िले में ही गायों की संख्या तीन लाख बढ़ गई है, 2000 महिलाओं को सिलाई से रोज़गार मिला है, किसानों से पूरा वर्ष 40 रू. किलो में सब्ज़ी ख़रीदते हैं तथा स्कूलों में 235 शिक्षक अपनी ओर से नियुक्त किए हुए हैं। अनेक गाँवों को गोबर गैस के बल पर एलपीजी मुक्त गाँव बनाया है।

मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुंदरम ने तीन दिन चली इस चर्चा में सबके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस चर्चा से हमें देश की भावी दिशा निर्धारित करने में लाभ मिलेगा। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता इस चर्चा को गाँव–गाँव तक ले जाएँगे। अफ्रीकी देश व ताइवान जैसे देश अपनी संकल्प शक्ति के बल पर आगे बढ़े हैं। भारत के पास युवा शक्ति, अनेक शोध संस्थान, स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, कृषि भूमि, लघु उद्योग आदि का विशाल तंत्र है। भारत भी अपनी संकल्प शक्ति के बल पर आगे बढ़ेगा। ग़रीबी मुक्त भारत, रोज़गार युक्त भारत, पर्यावरण की रक्षा करते हुए 2030 तक भारत 10 ट्रिल्यन डॉलर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। देश में इस संकल्प शक्ति और एकजुटता के निर्माण करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता गाँव–गाँव तक एक "महान जन अभियान" चलाएँगे।

कार्यक्रम के मुख्य आयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने तीन दिन चली चर्चा का सारांश प्रस्तुत किया।

इसी के साथ अर्थ चिंतन 2021 सम्पन्न हो गया। ❑❑

अमेजन खुलासे पर पांचजन्य को मिला आरएसएस का साथ

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन पर पांचजन्य द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीर बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग सरकार से की है। आईएएनएस से बातचीत करते हुए संघ के एक नेता ने कहा कि पांचजन्य की कवर स्टोरी में अमेजन पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वो काफी गंभीर है और इस सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए संघ मामलों के जानकार राजीव तुली ने कहा कि पांचजन्य की यह रिपोर्ट इंटरनल व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खुलासे पर आधारित है, इसलिए इसकी समुचित जांच कराना जरूरी है। राजीव तुली ने कहा कि इतनी बड़ी राशि केवल वकीलों पर या कंसलटेंसी के नाम पर खर्च करना कितना ठीक है, यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि अमेजन की वजह से छोटे व्यापारियों पर क्या असर पड़ा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही राजीव तुली ने इस पूरे मामले में अमेजन से भी अपना पक्ष रखने की मांग की।

आपको बता दें कि पांचजन्य ने इससे पहले आईटी कंपनी इंफोसिस पर भी एक कवर स्टोरी में कई तरह के आरोप लगाए थे। आईएएनएस ने इस पूरे मामले पर पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर से भी बातचीत की।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए पांचजन्य के संपादक ने कहा अमेजन कंपनी के ही एक मुखबिर ने यह खुलासा किया है कि कंपनी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक बड़ी राशि का इस्तेमाल किया है। यह सवाल अमेजन से पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो क्या गलत काम करता है, जो उसे रिश्वत देने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि अमेजन भारत के बाजार पर कब्जा करना चाहती है, अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहती है भारतीय संस्कृति पर भी आघात कर रही है , इसी तरह का काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया था।

इस बीच स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने पांचजन्य के खुलासे पर आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच 2015 से ही अमेजन के बारे में आवाज उठाता रहा है कि यह कंपनी गैरकानूनी तरीके से चोर दरवाजे से रिटेलिंग कर रही है।

उन्होंने कहा कि अमेजन गैरकानूनी रूप से काम करने के लिए भ्रष्टाचार और रिश्वत का सहारा ले रही है। यह हमारे देश के अर्थतंत्र पर कब्जा करना चाहती है और इसलिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 कहना बिल्कुल सही है।

https://www.newsnationtv.com/india/news/rss-panchjanya-amazon-213915.html

स्टार्टअप कंपनियों की 'फ्लिपिंग' देश की सुरक्षा के लिए खतराः एसजेएम

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने बड़ी स्टार्टअप कंपनियों की 'फ्लिपिंग' यानी देश के बाहर पंजीकरण को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। मंच ने कहा, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी गंतव्य का चयन करने पर कोष के स्रोत की जांच नहीं हो सकती है। इससे भारतीय उपभोक्ताओं का अहम ब्योरा विदेश चला जाता है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, एक अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाली यूनिकॉर्न की फ्लिपिंग से वे भारतीय नियामकीय निगरानी से बच सकती हैं। इससे देश के राजस्व का नुकसान होता है। उन्होंने कहा, भारत को इस बात का तो गर्व है कि उसके स्टार्टअप काफी मूल्यांकन हासिल कर रहे हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती। ऊंचे मूल्यांकन वाली ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां भारतीय नहीं रह गई हैं।

https://www.amarujala.com/india-news/rss-sjm-says-flipping-of-startup-companies-is-a-threat-to-the-security-of-the-country-read-other-important-news-of-the-country

स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की

स्वदेशी जागरण मंच उत्तराखंड की ओर से आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि सभी को अपने दैनिक जीवन में देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, इससे देश की आर्थिकी मजबूत होने के साथ–साथ लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। कहा आगामी दिनों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी को लेकर प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन किया जाएगा।

संघ दफ्तर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित कार्यशाला के समापन पर मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा स्वदेशी जागरण मंच ने आगामी 2030 तक बीपीएल फ्री भारत, सबको रोजगार के अवसर तथा देश की अर्थव्यवस्था को दस ट्रीलियन करने का लक्ष्य रखा है। कहा 30 वर्षों में डब्लूटीओ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह असफल रही है। राष्ट्र

की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने ओर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर स्वदेशी जागरण मंच आगामी दिनों में देश के सभी प्रांतों में मंच के कार्यकर्ताओं को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिये प्रशिक्षित करेगा, जो लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के लिये जागरुक करेंगे। किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एमएसपी कानूनी अधिकार बने, मंडी नेटवर्क मजबूत हो, जिला स्तर पर कृषि न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। किसान से माल खरीदने पर पेमेंट की गारंटी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मंच के क्षेत्रीय संयोजक राजीव कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में लोगों ने केवल सरकारी नौकारी को ही रोजगार मान लिया है, लेकिन यह सभी के लिए संभव नहीं है। कहा पहाड़ के लोग अपनी छोटी–मोटी जमीन बेचकर रोजगार के लिये पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, स्वदेशी जागरण मंच ऐसे लोगों को छोटे–छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिये प्रेरित करेगा, जिससे उन्हें अपने स्थान पर स्वरोजगार मिल सके। मौके पर मंच के सह संयोजक राम कुमार, प्रवीण पुरोहित, खेम सिंह चौहान, देवी प्रसाद नौटियाल आदि मौजूद थे।

https://www.livehindustan.com/uttarakhand/tehri/story-appealed-to-adopt-indigenous-goods-4568711.html

आत्मनिर्भरता के साथ देश को आगे ले जाने की जरूरत

विश्व में हमारी ताकत बढ़ी है इसका हमें अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। देश को संबल एवं ताकतवर बनाने के लिए हमें स्वदेशी से बने वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ना होगा।

यह विचार स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी में संघ के कोरिया विभाग के बौद्धिक प्रमुख संजय भारत ने

भारतीय मजदूर संघ के सभाकक्ष में व्यक्त की। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि स्वदेशी हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। जिससे हमारी लघु और कुटीर उद्योग गांव और शहरों में मजबूत बने चाइना के द्वारा निर्मित चाइनीज वस्तुओं से हम सभी को तौबा कर लेना चाहिए। मेक इन इंडिया मेक इंडिया के नारे को सशक्त और बुलंद करने का समय चल रहा है। चाइना के सामानों पर व्यापक पैमाने पर हम निर्भर हैं। हमें आत्मनिर्भरता के साथ देश को आगे ले कर जाना होगा। संभवतः इसी सोच को लेकर राष्ट्र ऋषि श्री ठेंगड़ी ने 22 नवंबर 1996 को स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की थी। स्वदेशी और विदेशी में फर्क कर हर घर–घर तक हमें अलख जगाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के संभाग संयोजक राजकिशोर चौधरी ने कहा की स्वदेशी की शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, अपने बच्चों अपने परिजनों के नाम से इसका प्रारंभ करना होगा। हमारे संस्कार राम, नारायण, श्याम, गीता, सीता लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का है। लेकिन हम अपने भारतीय परंपरा और संस्कार को भूलते जा रहे हैं। जब हम आचार विचार, व्यवहार और संस्कार से स्वदेशी होंगे तभी हम इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्वदेशी के लोग मातृभूमि से प्यार करते हैं।

कार्यक्रम का संचालन जिला महाविद्यालय प्रमुख अंशुमान तिवारी ने किया। इस अवसर पर संघ खंड प्रमुख जोगेश्वर राजवाडे, बजरंग दल के जिला संयोजक सुजीत सिंह, पूर्व नपा अध्यक्ष राजेश यादव, दीपेंद्र सिंह चौहान, दीपक दुबे, महेश गुप्ता, दीना नाथ यादव हरिनंदन पासवान, सरोज सिन्हा, जितेंद्र, शुभम मित्तल, जिला सह संयोजक अनुराग बघेल , जिला कोष प्रमुख नारायण राजवाड़े, एवं अन्य प्रमुख संघ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

https://www.naidunia.com/chhattisgarh/ambikapur-need-to-take-the-country-forward-with-selfreliance-7077985

80 से अधिक स्वावलंबी महिलाओं का सम्मान

स्वदेशी जागरण मंच की बटाला इकाई द्वारा दूसरे दिन आरडी खोसला डीएवी माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समारोह का आयोजन कर बड़ी संख्या में स्वावलंबी महिलाओं को स्वदेशी की अर्थ संबंधी धारणा से अवगत कराया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों से संबंधित 80 से ज्यादा स्वावलंबी महिलाओं का स्वदेशी जागरण मंच ने सम्मान किया। कार्यक्रम में शहर के नामी

उद्योगपति परमजीत सिंह गिल मालिक साहिल इंडस्ट्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सुआनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की संचालिका रणजीत कौर और प्रसिद्ध समाज सेवक अशोक भगत विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमृतसर विभाग के कार्यवाह रजत सरीन ने की। कार्यक्रम की अगुवाई स्वदेशी जागरण मंच बटाला जिला के जिला संयोजक दीपक वर्मा और नगर संयोजक कमलदीप लक्की ने की। कार्यक्रम कोआर्डिनेटर वरुण अग्रवाल ने कार्यक्रम को आयोजित करवाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा अर्थ चितन 2021 के अंतर्गत देशभर में वेबिनार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा संबंधी 23, 24 और 25 सितंबर को देश के नामी अर्थशास्त्रियों, केंद्रीय संस्थाओं के प्रमुखों एवं केंद्रीय मंत्रियों की उत्कृष्ट अगुवाई में स्वावलंबी व आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेते हुए चितन किया गया। वेबिनार का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच की केंद्रीय इकाई द्वारा किया गया। इसका प्रसारण देशभर में हुआ।

राष्ट्रीय सह संयोजक डा. अश्वनी महाजन ने कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को दिया जाने वाला धन केवल मात्र सहायता है ना कि रोजगार। गांव में रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। प्रसिद्ध समाज सेवक अशोक भगत ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि युवकों को नए विचार सृजित कर स्वयं का रोजगार शुरू करने की ओर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में जेएन शर्मा, झांसी की रानी सोसायटी की संतोष कुमारी, स्वदेशी जागरण मंच के प्रदीप महाजन, राजकुमार वर्मा, प्रोफेसर सुनील दत्त, मानिक, अंशुमन, मनीष होंडा, अशोक कुमार, राजन त्रेहन, महिला जिला संयोजिका नीलम महाजन ,सीमा बटालवी, गीता अग्रवाल, किरण चड्ढा, अनुराधा, रमेश वर्मा, हरिओम जोशी, गौतम, रितिका महाजन, मधु महाजन, पंकज गुप्ता, हीरा वालिया, राकेश कुमार ठेकेदार, वीना सोनी, पंकज शर्मा, अनिल भट्टी, पारस बामा,मोनू घई, पवन जोशी, अमनदीप कालिया, अंजू महाजन, सुषमा वर्मा, शैली शर्मा, अमनजोत वालिया आदि हाजिर थे।

https://www.jagran.com/punjab/gurdaspur-organizing-a-threeday-earth-chintan-program-by-swadeshi-jagran-manch-22057739.html

स्वदेशी जागरण मंच के अर्थ चिंतन कार्यक्रम का आयोजन

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से अर्थ चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटी की महामंत्री पंकज मित्तल ने किया।

मुख्य आयोजक कुलपति भगवती प्रकाश शर्मा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार व पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार ने विचार रखे।

मंच के बृज प्रांत के संयोजक डा.अमितेश अमित ने कहा कि ऑनलाइन वेबिनार को देश और विदेश में बड़ी संख्या में स्क्रिन लगाकर स्वदेशी कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध नागरिकों ने अर्थ चिंतन के विषय में जानकारी ली। कार्यक्रम में राजभूषण जौहरी, पंकज टंडन, राजकुमार सक्सेना, मुनीश परिहार, अरविन्द मिश्रा, पंकेश मिश्रा, ऋषभ शुक्ला, निश्चय त्रिवेदी आदि मौजूद रहे।

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/shahjahnpur/story-arth-chintan-program-organized-by-swadeshi-jagran-manch-4659295.html

भारतीय चीनी बढ़ाएगी एशियाई देशों की मिठास

वैश्विक बाजार में चीनी की मांग के मद्देनजर निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एशियाई देशों में चीनी की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय मिलों की चीनी ही सबसे सस्ती पड़ेगी। चीनी के प्रमुख उत्पादक देशों में गन्ने की खराब हुई फसल और चीनी उत्पादन में संभावित कमी को देखते हुए बाजार में तेजी का रुख बनने लगा है। इससे चालू पेराई सीजन (2021–22) के दौरान गन्ना किसानों और घरेलू चीनी उद्योग के दिन बहुरने वाले हैं। हालांकि इससे आने वाले महीनों में घरेलू बाजार में चीनी का दाम बढ़ भी सकता है। अंतरराष्ट्रीय चीनी बाजार में ब्राजील को चालू सीजन में धक्का लगेगा। महंगे तेल की वजह से वहां से होने वाली ढुलाई का खर्च बढ़ने से चीनी के महंगा होने का खतरा है।

इसी वजह से एशियाई देशों में ब्राजील की मिलों की चीनी के पहुंचने की संभावना कम हो गई है। दरअसल तेल के मूल्य में तेजी के मद्देनजर जहां एक ओर चीनी की ढुलाई महंगी पड़ेगी, वहीं ब्राजील चीनी की जगह एथनाल उत्पादन पर ज्यादा जोर दे सकता है। ढुलाई लागत अधिक होने की वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में इस बार ब्राजील की चीनी की जगह भारतीय चीनी पहुंचेगी। चीनी निर्यात की इस संभावना का लाभ उठाने के लिए घरेलू चीनी उद्योग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

एशिया में भारत के बाद थाइलैंड बड़ा चीनी उत्पादक है, जो इंडोनेशिया के बाजार को प्रभावित करता है। लेकिन थाइलैंड में लगातार दो वर्षो के सूखे ने चीनी उद्योग की हालत खराब कर रखी है। इसलिए वहां भी भारत से चीनी निर्यात की संभावना बनी हुई है। पड़ोसी देश होने के बावजूद बांग्लादेश ब्राजील से चीनी आयात करता रहा है। लेकिन इस बार उसे भी भारत से चीनी आयात करनी पड़ सकती है। वहां चीनी की घरेलू खपत 23 लाख टन है। मलेशिया में 18 लाख टन चीनी की घरेलू खपत है, जिसे आयात से पूरा किया जाता है। वियतनाम आमतौर पर अपनी जरूरत की 19 लाख टन चीनी आस्ट्रेलिया और थाइलैंड से आयात करता है। वहां इस बार भारतीय चीनी की धमक हो सकती है।

https://www.jagran.com/business/biz-indian-sugar-will-increase-the-sweetness-of-asian-countries-due-to-global-demand-22090500.html

गारमेंट्स, फुटवियर व फर्नीचर निर्यात के बड़े मौके

चीन में बिजली संकट गहराने से जहां कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल की किल्लत की आशंका गहरा रही है। लेकिन जो सेक्टर कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर नहीं हैं या बहुत कम निर्भर हैं, उनके लिए निर्यात में बढ़ोतरी के बड़े मौके बन रहे हैं। इनमें गारमेंट्स, फुटवियर व फर्नीचर जैसे सेक्टर प्रमुख हैं। हालांकि कुछ अन्य सेक्टर भी चीन के इस संकट का लाभ मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। मैन्यूफैक्चोरग प्रभावित होने की वजह से चीन गारमेंट्स, फुटवियर जैसे आइटम के निर्यात आर्डर छोड़ सकता है और वे आर्डर भारतीय कंपनियों को मिल सकते हैं।

गारमेंट व फुटवियर निर्माण से जुड़े कच्चे माल के लिए भारत की चीन पर निर्भरता काफी कम है, इसलिए इन वस्तुओं के निर्यात में समस्या नहीं आएगी और इनकी लागत नहीं बढ़ने से ये वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से मुकाबले में बनी रहेंगी। फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशंस (फियो) के प्रेसिडेंट ए. शक्तिवेल ने बताया कि निश्चित रूप से चीन के इस संकट का भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि गारमेंट के क्षेत्र में तो निर्यातकों के आर्डर बढ़ने लगे हैं।

अभी इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। शक्तिवेल इस संकट को भारत के लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं और वे फुटवियर जैसे क्षेत्र में भी इसके लाभ की संभावना जाहिर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स (ईपीसीएच) के चेयरमैन राजकुमार मल्होत्रा ने बताया कि हैं। डीक्राफ्ट्स निर्यात के क्षेत्र में चीन के संकट से सीधे तौर पर लाभ मिलना तो कठिन है।

फिर भी, दुनिया के बड़े सप्लायर चीन का उत्पादन ठप पड़ने से भारत को कई तरह से लाभ मिल सकता है। काउंसिल आफ लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के मुताबिक अगर फुटवियर के क्षेत्र में चीन की हिस्सेदारी कम होती है तो इसका लाभ भारत को मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन की तरह भारत में निर्यातकों के पास बड़ी मात्रा में उत्पादन की क्षमता नहीं है। फिर भी, अब तक चीन पर निर्भर अंतरराष्ट्रीय खरीदारों का रुख भारत की ओर हो सकता है।

https://www.jagran.com/business/biz-large-export-opportunities-for-sectors-less-dependent-on-china-sectors-like-garments-footwear-and-furniture-can-benefit-22090507.html

सरकार ने निपटाई 72 फीसद उधारी

केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 40 हजार करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए दिए हैं। इस कारोबारी साल में सरकार अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 15 जुलाई 2021 को 75000 करोड़ रुपए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए थे। इस रकम के साथ केंद्र अब तक 72 फीसद रकम की अदायगी कर चुका है। उसे कुल 1.59 लाख करोड़ रुपए की अदायगी करनी है। बाकी रकम का केंद्र सरकार धीरे–धीरे निपटारा करेगी।

सरकार हर दूसरे महीने रकम का निपटारा कर रही है। 28 मई को हुई 43वीं जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग में केंद्र सरकार ने 2021–22 के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपए उधार लिए थे। ❑❑

https://www.jagran.com/business/biz-centre-releases-40000-crore-to-states-as-back-to-back-loan-for-gst-shortfall-22091616.html

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांतीय विचार वर्ग, दक्षिण बिहार

(7–8 सितंबर, 2021)

सचित्र झलक

प्रांतीय विचार वर्ग, सौराष्ट्र

(12 सितंबर, 2021)

स्वदेशी सप्ताह

(25 सितंबर – 3 अक्टूबर 2021)

नागपूर, महाराष्ट्र

जमुई, बिहार

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अक्टूबर 2021
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

केंद्रीय कार्यसमिति बैठक, नई दिल्ली

(18–10 सितंबर, 2021)

सचित्र झलक

प्रांतीय विचार वर्ग, उत्तराखंड

(11–12 सितंबर, 2021)

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती